सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
You Tube

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 01, अंक 329, नई दिल्ली | बुधवार, 07 फरवरी 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा ।

03 मंत्री-विधायक सरकारी स्कूलों में बच्चों का करवा रहे एडमिशन
06 चुनावी साल का संयमित बजट
08 भाजपा ने जिले में किया लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद

संक्षेप...

बेहतर से बदतर हालत में पहुंची प्रगति मैदान सड़क टनल...

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने प्रगति मैदान सुरंग सड़क में घटिया काम पर निर्माणकर्ता कंपनी एलएंडटी (लार्सन एंड टूब्रो) को 500 करोड़ का कानूनी नोटिस भेजा है। एलजी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को विभाग के संबंधित अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहा है।

नईदिल्ली। एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने प्रगति मैदान सुरंग सड़क में घटिया काम पर निर्माणकर्ता कंपनी एलएंडटी (लार्सन एंड टूब्रो) को 500 करोड़ का कानूनी नोटिस भेजा है। एलजी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को विभाग के संबंधित अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहा है।

हो रहा जल भराव

विभाग ने कंपनी को दिए नोटिस में उन मुद्दों को उठाया है, जिनके कारण एक बेहतर परियोजना बदतर हालत में पहुंच गई है। इसमें मुख्य मुद्दा सुरंग सड़क में हो रहे जल भराव को लेकर उठाया गया है।

एलएंडटी ने परियोजना पर काम किया था, जिसमें परियोजना के डिजाइन की एलएंडटी की जिम्मेदारी थी। इसमें डिजाइन संबंधी खामियां सामने आई हैं। विभाग ने समस्याएं दूर कराने के लिए कंपनी को 15 दिन का समय दिया है।

पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन

सुरंग सड़क का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19 जून 2022 को किया था। उद्घाटन के कुछ समय के बाद से लगातार इसमें पानी का रिसाव हो रहा है। सुरंग की दीवारें खराब हो रही हैं। गत 17 जनवरी को एलजी वीके सक्सेना ने प्रगति मैदान सुरंग सड़क का निरीक्षण किया था।

जल भराव और रिसाव का मुद्दा उठाया

एलजी ने पाया था कि सुरंग सड़क जल जमाव और रिसाव के मुद्दों का सामना कर रही है। इससे नाराज एलजी के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने एलएंडटी को कानूनी नोटिस जारी किया है, जिसमें प्रतिष्ठा को नुकसान तथा आश्वासन के बावजूद निष्क्रियता के लिए 500 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

एलजी ने इससे पहले अगस्त 2023 और सितंबर 2023 में भी सुरंग का निरीक्षण किया था और दौरे में तीनों बार एलएंडटी के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। एलएंडटी को भी जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने को कहा गया। अभी तक जल रिसाव की समस्या का निदान न करने पर एलजी ने मुख्य सचिव और पीडब्ल्यूडी क सचिव को परियोजना पर प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण करने में विफलता के लिए अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा जुड़ेगा नोएडा एयरपोर्ट

एनसीआर में 31 किमी लंबा बन रहा एक और मार्ग

एयरपोर्ट तक यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी के विभिन्न विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे के अलावा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके लिए बल्लभगढ़ से नोएडा एयरपोर्ट तक 31 किमी लंबी सड़क का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) कर रहा है। एयरपोर्ट की दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से कनेक्टिविटी के लिए बन रहे मार्ग का कार्य अप्रैल तक पूरा होना है।

संजय बाटला

ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अक्टूबर में यात्री सेवाओं की शुरूआत होगी। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए सड़क परियोजनाओं पर काम हो रहा है, रेलवे कनेक्टिविटी के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। कनेक्टिविटी परियोजना के कार्य में तेजी आने के लिए नौ फरवरी को एयरपोर्ट की निर्माण साइट पर समीक्षा बैठक होगी।

अप्रैल तक बन जाएगा नया मार्ग

इसकी अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल करेंगे। बैठक में रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अलावा यमुना प्राधिकरण व नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. नियाल के अधिकारी शामिल होंगे। एयरपोर्ट की दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से कनेक्टिविटी के लिए बन रहे मार्ग का कार्य अप्रैल तक पूरा होना है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री सेवाओं की शुरुआत होने में मात्र सात माह का समय बचा है। विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. के साथ हुए अनुबंध के तहत उसे 29 सितंबर तक कार्य पूरा करना है। एयरपोर्ट तक यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी के विभिन्न विकल्प तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर यात्री सेवाओं की शुरुआत होने तक सड़क कनेक्टिविटी ही मिल सकेगी।

बल्लभगढ़ से नोएडा तक बन रही सड़क

यमुना एक्सप्रेस-वे के अलावा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके लिए बल्लभगढ़ से नोएडा एयरपोर्ट तक 31 किमी लंबी सड़क का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) कर रहा है। इंटरचेंज के माध्यम से यह मार्ग सीधे एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार से जुड़ेगा। इंटरचेंज का निर्माण भी एनएचएआई कर रहा है।

एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल को चोला रेलवे स्टेशन से जोड़ने व आर्बिटल रेलवे से भी जोड़ने की योजना है। इसके अलावा दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल, नमो भारत रेल आदि से भी नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने की योजना है। इसकी डीपीआर तैयार हो रही है। यमुना व ईपीई को जोड़ने के लिए भी इंटरचेंज का निर्माण हो रहा है।

यमुना प्राधिकरण एवं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए नौ फरवरी को बैठक होगी। इसमें परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

दिल्ली परिवहन विभाग का सर्वर हुआ सामान्य, बीते पांच दिनों से था ठप

दिल्ली परिवहन विभाग का सर्वर फिर से शुरू हो गया है। अब लोगों को लाइसेंस बनवाने में कोई परेशानी नहीं होगी।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट का सर्वर अब फिर से चलने लगा है। इस सर्वर के न चलने की वजह से लोगों के लाइसेंस नहीं बन पा रहे थे। बताया जा रहा है कि यह समस्या गुरुवार से आ रही थी। लाइसेंस बनवाने के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय पर पहुंचे लोगों को मंगलवार यानी आज आने के लिए बोला गया है। आज वेबसाइट का सर्वर सही ढंग से चल रहा है।

सर्वर न चलने से बढ़ी परेशानी

परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक, राजधानी में रोजाना कई लोग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं। लेकिन सर्वर न चलने की वजह से परेशानी बढ़ती जा रही थी। अब लोगों का लाइसेंस बनवाने का इंतजार खत्म होगा। क्षेत्रीय कार्यालय पर पहुंचे लोगों से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अधिकारियों ने आज से वेबसाइट फिर से शुरू हो गई है। अब वह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे।

लाइसेंस बनवाने आए शख्स को हुई परेशानी

सराय काले खां में लाइसेंस बनवाने के लिए एक शख्स टेस्ट देने के लिए पहुंचा था, इसके लिए उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी। लेकिन सर्वर न चलने के कारण उनका टेस्ट नहीं हो पाया। अब उन्हे फिर से टेस्ट देने के लिए छुट्टी लेकर आना पड़ेगा। लाइसेंस के लिए टेस्ट देने आए सैकड़ों लोगों को परेशानी हो रही है। जब इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते सर्वर नहीं चल पा रहा है। हमारी वेबसाइट का सर्वर जल्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद लोगों का काम होना भी शुरू हो जाएगा।

आवेदनों की छंटनी शुरू, 31 मार्च तक जारी होंगे ई-टैक्सी के 500 परमिट

नई दिल्ली। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत बेरोजगारों को ई-टैक्सी परमिट देने की योजना के तहत आवेदनों की छंटनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला और उपमंडल स्तर पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को आवेदनों की छंटनी का जिम्मा सौंपा गया है। छंटनी के बाद क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अपनी रिपोर्ट परिवहन निदेशालय को भेजेंगे। 31 मार्च तक आवेदकों को ई-टैक्सी परमिट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। ई-टैक्सी योजना के पहले चरण में 500 परमिट दिए जाने हैं। परिवहन विभाग के पास अब तक तीन हजार से अधिक आवेदन आ चुके हैं। जिन आवेदकों को पहले चरण में परमिट नहीं मिलेंगे, उन्हें दूसरे चरण में प्राथमिकता दी जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को 15 दिन के भीतर आवेदनों की छंटनी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सबसे पहले आवेदकों के दस्तावेज जांचेंगे। इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। आवेदक को खुद ही ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। सरकार के सख्त निर्देश हैं कि जो व्यक्ति परमिट के लिए आवेदन करेगा, उसे ही अपनी ई-टैक्सी चलानी होगी। अगर आवेदक टैक्सी चलाने के लिए किसी अन्य को नौकरी पर रखता है या कोई करार करता है तो परमिट रद्द कर दिया जाएगा।

दिल्ली-NCR के लोगों के लिए गुड न्यूज, नोएडा से गोवा का सफर होगा आसान; मिलेगी सीधी फ्लाइट

परिवहन विशेष न्यूज

एक तरफ गोवा पर्यटन विभाग रिजेनरेटिव पर्यटन का नया मॉडल लांच कर रहा है वहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों को गोवा से सीधे जोड़ने के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रयासरत है। ये बातें उन्होंने गोवा की आजादी की 62वीं वर्षगांठ के मौके पर गोवा पर्यटन विभाग की तरफ से पर्यटकों के लिए रिजेनरेटिव पर्यटन मॉडल लांच करने के मौके पर कही।

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोवा के लिए भी विमान सेवा शुरू होगी। इसके लिए गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे ने दो एयरलाइंस कंपनियों के साथ बातचीत की है। उनका कहना है कि दिल्ली एनसीआर का बड़ा तबका गोवा में घूमने के लिए आता है।

एक तरफ गोवा पर्यटन विभाग रिजेनरेटिव पर्यटन का नया मॉडल लांच कर रहा है, वहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों को गोवा से सीधे जोड़ने के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रयासरत है। ये बातें उन्होंने गोवा की आजादी की 62वीं वर्षगांठ के मौके पर गोवा पर्यटन विभाग की तरफ से पर्यटकों के लिए रिजेनरेटिव पर्यटन मॉडल लांच करने के मौके पर कही।

गोवा का नया रोडमैप पेश

1980 के विश्व पर्यटन के प्रसिद्ध मनीला घोषणा पत्र और जी-20 पर्यटन मंत्रियों के कार्य समूह की बैठक के मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ खुद को जोड़ते हुए गोवा पर्यटन विभाग ने पर्यटन के लिए गोवा का नया रोडमैप पेश किया। गोवा में पर्यटन का यह बदला मॉडल भारत में पुनर्योजी पर्यटन के लिए नए मॉडल का कार्य करेगा।

रोहन खुंटे ने कहा कि एकादश तीर्थ के शुभारंभ के साथ, हम आध्यात्मिकता, स्वदेशीता, सांस्कृतिक और सभ्यतागत राष्ट्रवाद और जागरूक पर्यटन पर जोर देते हुए भारतीय पर्यटन को एक नया रूप दे रहे हैं। यात्रा और तीर्थ यात्रा के माध्यम से

> रोहन खुंटे ने कहा कि एकादश तीर्थ के शुभारंभ के साथ, हम आध्यात्मिकता, स्वदेशीता, सांस्कृतिक और सभ्यतागत राष्ट्रवाद और जागरूक पर्यटन पर जोर देते हुए भारतीय पर्यटन को एक नया रूप दे रहे हैं। यात्रा और तीर्थ यात्रा के माध्यम से भारतीय लोगों ने पूरे सहस्राब्दी में अपने भौगोलिक ज्ञान का विस्तार किया है...

भारतीय लोगों ने पूरे सहस्राब्दी में अपने भौगोलिक ज्ञान का विस्तार किया है, खुद को क्षेत्रवाद और संकीर्णतावाद की बाधाओं से मुक्त किया है। हम पर्यावरण, संस्कृति और समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं।

पर्यटन के मामले में इन शहरों से हैं चुनौतियां

इस मॉडल को पेश करने में हमारा लक्ष्य यात्रा और ऐसे पर्यटन क्षेत्र को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो पर्यावरण और मानव आबादी दोनों को लाभ पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन के मामले में हमारी चुनौतियां थाईलैंड, इंडोनेशिया, कुआलालंपुर और बैंकाक जैसे आधुनिक शहरों से है।

गोवा ने कोरोना के बाद नए समाधानों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। प्रौद्योगिकी अपनाने के साथ पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के साथ स्थानीय लोग और समुदायों को स्वावलंबी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गोवा सिर्फ समुद्र-तट केंद्रित पर्यटन मॉडल से अधिक कुछ और भी है।

गोवा के पर्यटन निदेशक सुनील अंचीपका ने बताया कि पर्यटन विभाग का उद्देश्य गोवा को सिर्फ समुंद्र तट के किनारे (बीच) का पर्यटन दिखाना नहीं, बल्कि गोवा में समुंद्र तट के अलावा एकादश तीर्थ के रूप में पहचान देना है। एकादश तीर्थ को सबके सामने लाए जाने का प्रयास स्थानीय लोग और स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है।

निर्धारित अवधि में लागत की प्रतिपूर्ति के लिए टोल शुल्क में कितनी वृद्धि की जरूरत है।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर कितना बढ़ेगा टोल टैक्स?

इस दिन होगा फैसला; प्राधिकरण ने कंपनी से मांगी रिपोर्ट

यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने कंपनी के प्रस्ताव पर फैसला करने के बजाए कंपनी से टोल दरों में वृद्धि की वजह बताते हुए रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में कंपनी को बताना होगा कि एक्सप्रेस वे की निर्माण लागत कितनी थी। बता दें कि टोल दरों को लेकर 26 फरवरी को यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में फैसला होगा।

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस वे की टोल दरों को लेकर 26 फरवरी को यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में फैसला होगा। आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट आवंटन को लेकर होने वाली बैठक से पहले यमुना प्राधिकरण ने जेपी इंफ्राटेक से रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में कंपनी को टोल शुल्क में बढ़ोतरी के प्रस्ताव की वजह तार्किक रूप स्पष्ट करनी होगी।

प्राधिकरण ने वृद्धि की मांगी वजह

जेपी इंफ्राटेक ने टोल दरों में वृद्धि के लिए यमुना प्राधिकरण को प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को प्राधिकरण की 79 वीं बोर्ड बैठक में रखा गया था, लेकिन बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर फैसला करने के बजाए कंपनी से टोल दरों में वृद्धि की वजह बताते हुए रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में कंपनी को बताना होगा कि एक्सप्रेस वे की निर्माण लागत कितनी थी। एक्सप्रेस वे की शुरुआत में यातायात को लेकर क्या पूर्वानुमान लगाया गया था। इसके सापेक्ष यातायात की स्थिति क्या है। इससे प्राप्त होने वाले टोल शुल्क की प्रतिशत दर कितनी है। यातायात के पूर्वानुमान के अनुसार, कंपनी एक्सप्रेस वे की निर्माण लागत कब तक प्राप्त कर लेगी। 36 साल की अनुबंध अवधि पूरा होने तक उसे कितना राजस्व मिल चुका होगा।

26 फरवरी को होगी बोर्ड की बैठक

निर्धारित अवधि में लागत की प्रतिपूर्ति के लिए टोल शुल्क में कितनी वृद्धि की जरूरत है। एक्सप्रेस वे के रखरखाव व पर होने वाले खर्च के अलावा नोएडा एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने पर एक्सप्रेस वे पर बढ़ने वाले यातायात के पूर्वानुमान एवं उससे प्राप्त होने वाले टोल शुल्क, टोल वसूली की अवधि 15 साल बढ़ाने पर यातायात व टोल शुल्क आदि की जानकारी देनी होगी। यमुना प्राधिकरण सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि टोल दर वृद्धि को लेकर मांगी गई रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण बोर्ड आगामी 26 फरवरी को होने वाली बैठक में विचार करेगा।

टोल दरों में प्रस्तावित वृद्धि रुपये प्रति किमी

श्रेणी	वर्तमान	प्रस्तावित
दो, तीन पहिया व ट्रैक्टर	1.25	1.50
कार, जीप, हल्के वाहन	2.50	2.95
हल्के व्यवसायिक वाहन	3.90	4.60
बस, ट्रक	7.85	9.35
भारी वाहन तीन से छह धुरीय	11.90	14.25
छह व उससे अधिक धुरीय	15.40	18.35

इनसाइड

प्रेग नेंसी में मोबाइल रेडिएशन से दूरी बनाना जरूरी वरना शिशु को हो सकता है मेंटल प्रॉब्लम

अगर गर्भवती महिला के आसपास अत्यधिक मोबाइल रेडिएशन है, तो उसके पेट में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है. यही नहीं, बच्चे को जीवन भर बिहेवियर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है. जानें, प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल रेडिएशन से अजन्मे बच्चे के विकास में क्या समस्या आ सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है. हम सभी सुनते आए हैं कि अधिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है. खासतौर पर प्रेग्नेंट महिला और उसके पेट मे पल रहे बच्चे के लिए ये और भी खतरनाक हो सकता है. प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से पेट में पल रहे बच्चे के विकास पर बुरा असर पड़ता है और इसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी तक हो सकती है. केवल मां ही नहीं, अगर मां के आस पास लोग वायरलेस चीजों का अधिक इस्तेमाल कर रहे है तो इसका भी भ्रूण में पल रहे बच्चे पर खराब असर पड़ सकता है. मॉमजंक्शनमें छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में किए गए शोध में पाया गया है कि अत्यधिक मोबाइल रेडिएशन में अगर गर्भवती मां रहती है तो जन्म के बाद बच्चे को जीवन भर बिहेवियर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है. यही नहीं, इसकी वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. तो आइए जानते हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं.

वायरलेस डिवाइस कैसे करता है प्रभावित

दरअसल जब हम मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी तरह के वाइफाई या वायरलेस डिवाइस के संपर्क में आते हैं तो इससे हर वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स निकलते रहते हैं. ये वेव्स हमारे शरीर के डीएनए को डैमेज करने की क्षमता रखते हैं और हमारे शरीर में बन रहे जीवित सेल्स के मोलक्यूल्स को बदल सकते हैं. जिसका असर लॉग टर्म काफी खतरनाक हो सकता है. चूंकि भ्रूण हर वक्त ग्रोथ कर रहा है ऐसे में उसके डीएनए और लीविंग सेल्स आसानी से इसकी चपेट में आ सकते हैं. जिसका दूरगामी असर भी काफी खतरनाक हो सकता है.

क्या कहता है शोध

अलग अलग शोधों में पाया गया कि मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चे पर कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन अगर मां और बच्चा 24 घंटे मोबाइल रेडिएशन के बीच हैं तो बच्चे की मेमोरी, ब्रेन ग्रोथ और बिहेवियर में खतरनाक रूप से समस्या आ सकती है. शोधों में यह भी पाया किया गया कि प्री और पोस्ट डिलीवरी के बाद ऐसे बच्चों में हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है जो समय के साथ बढ़ती जाती है. यही नहीं, बच्चे की भाषा, संचार पर भी इसका बुरा असर पड़ता है.

इस तरह करें बचाव

- घर में जहां तक हो सके वाई फाई या ब्लूटूथ उपकरणों का इस्तेमाल कम करें.
- बेहतर होगा अगर आप मोबाइल की बजाय लैंड लाइन फोन का इस्तेमाल करें.
- रेडियो, माइक्रोवेव, एक्सरे मशीन आदि से दूरी बनाएं.
- मोबाइल टावर आदि के आस पास घर ना लें.

गर्भावस्था में मोबाइल के नुकसान

-गर्भवती महिलाओं में रेडिएशन से मस्तिष्क की गतिविधि पर भी प्रभाव पड़ सकता है जिससे थकान, चिंता और नींद में रुकावट पैदा होती है.
-गर्भावस्था के दौरान रेडियो वेव्स के लगातार संपर्क से आगे जाकर कैंसर का खतरा बन सकता है.
-मां गर्भावस्था के दौरान फोन का अधिक इस्तेमाल करे या काफी करीबी लोग घर पर इसका इस्तेमाल करें तो बच्चे के व्यवहार में 50 प्रतिशत बदलाव देखने को मिलता है.
-ऐसे बच्चे अधिक एग्रेसिव और हाइपरटेंशन के पेशेंट हो जाते हैं.
-शारीरिक और मानसिक एक्टिविटी में काफी कमी देखने को मिलती है. याददाश्त भी कम हो जाती है. अगर आपके बच्चे में किसी तरह की समस्या आ रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें.

5 डेली लाइफ की चीजें महिलाएं जरूर सीख लें, मदद की नहीं पड़ेगी जरूरत, कदम से कदम मिलाकर चलें जमाने के साथ

जीवन में कुछ बुनियादी कौशल हैं, जिन्हें हर महिला को सीखना ही चाहिए. इन्हीं कौशलों में से एकाध हैं बच्चों की परवरिश, खाना बनाना आदि. लेकिन, आपको यह जानना जरूरी है कि इन चीजों के अलावा भी कई चीजे हैं, जिसे जल्द से जल्द सीखना महिलाओं के लिए जरूरी होता है. इन चीजों को अगर आप सीख लें तो लोगों पर निर्भरता आपकी कम होगी और आप लोगों से मदद मांगने की बजाय, उनकी मदद कर सकेंगी. जानते हैं कि बेहतर जीवन के लिए हर महिला को डेली लाइफ में किन प्रैक्टिकल स्किल को सीखना जरूरी है.

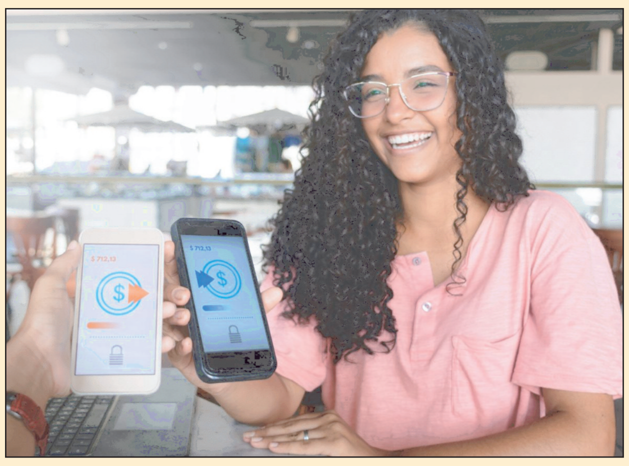

1/5 बेसिक स्किल के रूप में हर महिला को ड्राइविंग के अलावा टायर और इंजन ऑयल बदलना भी सीखना जरूरी है. जितना जरूरी महिलाओं के लिए ड्राइविंग सीखना होता है, अपनी गाड़ी से जुड़ी हर बात की जानकारी रखना भी लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है. मान लें कि आप कभी आप किसी ट्रैवल में हों और आपका टायर पंचर हो जाए और आपका मोबाइल काम ना करे. ऐसे में आप खुद ही गाड़ी का टायर बदल सकती हैं. वरना मदद के चक्कर में आप बुरे लोगों की चंगुल में आ सकती हैं.

Image : Canva

बेसिक स्किल के रूप में हर महिला को ड्राइविंग के अलावा टायर और इंजन ऑयल बदलना भी सीखना जरूरी है. जितना जरूरी महिलाओं के लिए ड्राइविंग सीखना होता है, अपनी गाड़ी से जुड़ी हर बात की जानकारी रखना भी लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है. मान लें कि आप कभी आप किसी ट्रैवल में हों और आपका टायर पंचर हो जाए और आपका मोबाइल काम ना करे. ऐसे में आप खुद ही गाड़ी का टायर बदल सकती हैं. वरना मदद के चक्कर में आप बुरे लोगों की चंगुल में आ सकती हैं.

2/5 विनम्र तरीके से और दृढ़तापूर्वक किसी को ना कहना सीखना हर महिला को आना चाहिए. अगर आप किसी को ना नहीं कह पाती हैं तो आपको जल्द से जल्द यह सीखने की जरूरत है. इस तरह आप अपने साथ होने वाली कई अनहोनी घटनाओं को होने से रोक सकेंगी. अगर कोई आपको कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है जिसे आप नहीं करना चाहती हैं तो आपको खुद के लिए खड़े होना सीखना होगा और 'ना' कहना होगा.
विनम्र तरीके से और दृढ़तापूर्वक किसी को ना कहना सीखना हर महिला को आना चाहिए. अगर आप किसी को ना नहीं कह पाती हैं तो आपको जल्द से जल्द यह सीखने की जरूरत है. इस तरह आप अपने साथ होने वाली कई अनहोनी घटनाओं को होने से रोक सकेंगी. अगर कोई आपको कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है जिसे आप नहीं करना चाहती हैं तो आपको खुद के लिए खड़े होना सीखना होगा और 'ना' कहना होगा.

3/5 अगर आप बजट बनाना और अपने पैसों का सही निवेश करना सीख जाती हैं, तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करेंगी. अगर आप यह सीख जाएं कि कैसे अपने पैसे को इनवेस्ट करना है, तो आप जो कुछ भी जीवन में करना चाहती हैं, उसके लिए खुद पैसा पैदा भी कर सकती हैं. अगर आप बजट बनाना और अपने पैसों का सही निवेश करना सीख जाती हैं, तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करेंगी. अगर आप यह सीख जाएं कि कैसे अपने पैसे को इनवेस्ट करना है, तो आप जो कुछ भी जीवन में करना चाहती हैं, उसके लिए खुद पैसा पैदा भी कर सकती हैं.

4/5 अगर आप कुकिंग नहीं जानतीं तो आपको कदम कदम पर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है. यही नहीं, आप चाहकर भी किसी को अपने हाथ से बना कुछ स्पेशल नहीं खिला पाएंगी. ऐसे में कम से कम 3 कंप्लीट डिश आप जरूर बनाना सीखें. यही नहीं, यह भी प्रयास करें कि आप रोज खाने वाले आसान डिश को भी बनाना सीख जाएं. इससे आपको हर बार बाहर के खाने को ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप हेल्दी रहेंगी.
अगर आप कुकिंग नहीं जानतीं तो आपको कदम कदम पर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है. यही नहीं, आप चाहकर भी किसी को अपने हाथ से बना कुछ स्पेशल नहीं खिला पाएंगी. ऐसे में कम से कम 3 कंप्लीट डिश आप जरूर बनाना सीखें. यही नहीं, यह भी प्रयास करें कि आप रोज खाने वाले आसान डिश को भी बनाना सीख जाएं. इससे आपको हर बार बाहर के खाने को ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप हेल्दी रहेंगी.

5/5 हर महिला को यह पता होना चाहिए कि आंधी के बीच, अंधेरे में किसी अपरिचित जगह पर कैसे ड्राइव करना या रास्ता ढूंडना है. अगर आप कभी खो जाएं तो अपना रास्ता कैसे खोजें. अगर आपका जीपीएस टूट जाए और रास्ता बताने के लिए कोई ना हो तो किस तरह मैप की मदद से जगह को ढूंडें.अगर आप इस तरह के कौशल को अपने अंदर पैदा कर लें तो यकीन मानिए, आप अधिक फ्री महसूस करेंगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.
हर महिला को यह पता होना चाहिए कि आंधी के बीच, अंधेरे में किसी अपरिचित जगह पर कैसे ड्राइव करना या रास्ता ढूंडना है. अगर आप कभी खो जाएं तो अपना रास्ता कैसे खोजें. अगर आपका जीपीएस टूट जाए और रास्ता बताने के लिए कोई ना हो तो किस तरह मैप की मदद से जगह को ढूंडें.अगर आप इस तरह के कौशल को अपने अंदर पैदा कर लें तो यकीन मानिए, आप अधिक फ्री महसूस करेंगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

वर्किंग वुमन के लिए बेस्ट हैं ये हेल्थ केयर टिप्स, 5 आसान तरीके करें फॉलो, हमेशा रहेंगी फिट और हेल्दी

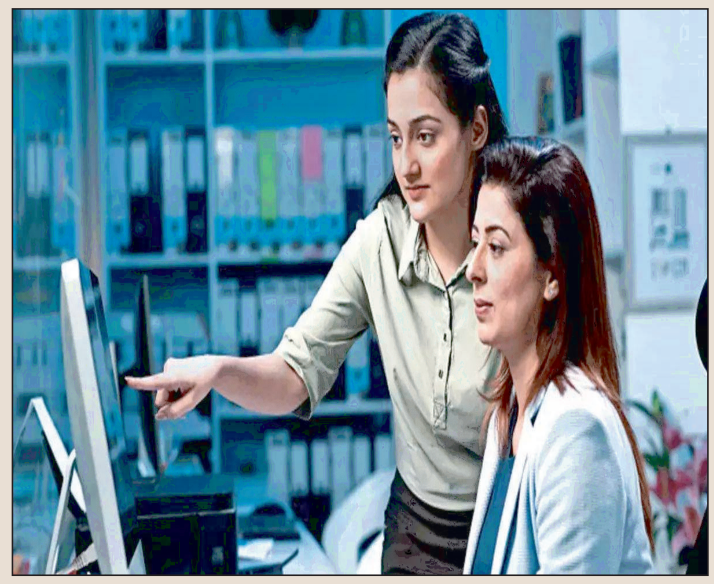

रोजमर्रा की बिजी लाइफस्टाइल में ज्यादातर महिलाओं को अपने लिए समय नहीं मिल पाता है. खासकर वर्किंग वुमन के लिए घर और ऑफिस को संभालना काफी मुश्किल टास्क होता है. हालांकि वर्किंग वुमन अगर चाहें तो कुछ आसान तरीकों की मदद से ना सिर्फ घर और बाहर की जिम्मेदारियों के बीच में अपना खास ख्याल रख सकती हैं बल्कि खुद को फिट और हेल्दी भी बना सकती हैं.
घर और ऑफिस का काम करते समय महिलाएं अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं. जिसके चलते आप कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी शिकार हो सकती हैं. इसलिए हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वर्किंग वुमन के लिए कुछ आसान हेल्थ केयर टिप्स, जिसे फॉलो करके आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फुल एन्जॉय कर सकती हैं.

हैवी नाश्ता करें

काम में बिजी होने के कारण कई बार वर्किंग वुमन को खाने का समय नहीं मिल पाता है. ऐसे में आप सुबह हैवी नाश्ता कर सकती हैं. इससे ना सिर्फ आपका पेट भरा रहेगा बल्कि काम के दौरान आपको भूख का भी कम अहसास होगा और आप काम पर पूरा फोकस कर पाएंगी.

हेल्दी डाइट लें

वर्किंग वुमन अक्सर भूख लगने पर जंक फूड या तला-भुना खाकर पेट भर लेती हैं. जिससे आपके शरीर में पोषण की कमी होने लगती है और आप बीमार भी पड़ सकती हैं. इसलिए हमेशा घर का खाना खाने पर जोर दें. साथ ही डाइट में दही, सीजनल फ्रूट्स और हरी सब्जियों जैसी न्यूट्रिएंट्स रिच चीजों का सेवन करें. जिससे आप फिट और हेल्दी रह सकेंगी.

भरपूर पानी पिएं

वर्किंग वुमन अक्सर काम में उलझकर समय पर पानी पीना भी भूल जाती हैं. जिससे आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकती हैं. इसलिए काम के दौरान बीच-बीच में पानी जरूर पीएं. वहीं दिन में 8-10 गिलास पानी पीकर आप खुद को हाइड्रेटेड और एनर्जेटिक रख सकती हैं.

तनाव मुक्त रहें

घर और ऑफिस का काम मैनेज करने के चक्कर में कई बार महिलाएं स्ट्रैस लेने लगती हैं. जिससे ना सिर्फ आपका मूड खराब हो जाता है बल्कि काम में भी पूरी तरह से मन नहीं लग पाता है. इसलिए काम के बीच में खुद को खुश रखने की कोशिश करें. जिससे आप तनाव मुक्त रह सकेंगी.

अपनी लाइफ में शामिल स्पेशल लेडीज को दें ये खास गिफ्ट, पाते ही खिल उठेगा उनका खूबसूरत चेहरा

प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को पूरी दुनिया में 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' सेलिब्रेट किया जाता है. हर साल यह दिवस एक खास थीम को ध्यान में रखकर मनाया जाता है. वर्ष 2023 की थीम 'एम्ब्रेसइक्विटी' (Embrace Equity) रखी गई है. 8 मार्च 1975 को युनाइटेड नेशंस द्वारा 'इंटरनेशनल वुमेंस डे' को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी. घर-परिवार, समाज आदि में महिलाओं की भागीदारी, उपस्थिति, योगदान और उनकी ताकत को सराहने, जश्न मनाने का दिन है महिला दिवस. महिला दिवस पर आप अपनी जिंदगी में मौजूद हर एक स्पेशल लेडी को खास गिफ्ट देकर ये जता सकते हैं कि आपकी लाइफ में उनका कितना महत्व है. डालें कुछ शानदार गिफ्ट्स आइटम पर एक नजर.

किताबें- कई महिलाएं किताबों की बेहद शौकीन होती हैं. उन्हें अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ने का शौक होता है. यदि आपके घर में आपकी मां, बहन, मौसी, चाची या फिर दोस्त को किताबें पढ़ने का शौक है, उन्हें सहेजना, कलेक्ट करने की हॉबी है तो फिर बुक्स से बेहतर उनके लिए कोई दूसरा सामान नहीं हो सकता है. यह एक ऐसा तोहफा है, जो वर्षों आपके साथ रहता है. आप चाहें तो फिक्शन-नॉन फिक्शन, कॉमेडी, कविता, उपन्यास, कला और साहित्य जगत से संबंधित कोई भी किताब गिफ्ट कर सकते हैं. आप उनकी फेवरेट राइटर की किताब देंगे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी.
हरे-भरे पौधे करें गिफ्ट- आजकल गिफ्ट्स में एक-दूसरे को तरह-तरह के प्लांट्स देने का ट्रेंड भी काफी बढ़ गया है. यह एक बेहतरीन गिफ्ट आइडिया इसलिए भी है, क्योंकि इसे देखते ही सामने वाले का मूड फ्रेश हो जाएगा. घर में हरियाली होने से पॉजिटिव सोच और एनर्जी भी मिलती है. घर का वातावरण फ्रेश बना रहता है. यदि आपके घर में किसी भी लेडी को प्लांट लगाने और इंडोर पौधे रखने का शौक है तो ये गिफ्ट उन्हें जरूर दें. साथ ही आप फूलों का गुलदस्ता भी दे सकते हैं.
गिफ्ट हैंपर दें- आजकल हैंपर देने का भी ट्रेंड खूब है. लोग अपनों को उनके फेवरेट आइटम्स को एक साथ पैक करा कर हैंपर तैयार कराते हैं और स्पेशल ओकेजन पर बतौर तोहफा प्रजेंट करते हैं. आप भी हैंपर में मेकअप आइटम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स आदि चीजें मिक्स-मैच करके डलवाएं और अपनी फेवरेट लेडी को वुमेंस डे पर गिफ्ट करते हुए इस दिन की ढेरों बधाई दें.
घड़ी, मोबाइल करें गिफ्ट- यदि आपकी बहन, मां या फिर दोस्त को घड़ी या मोबाइल की जरूरत है तो उन्हें ये गिफ्ट देकर उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं. हो सकता है आपकी बहन या मम्मा का मोबाइल सही से चल ना रहो हो और उन्हें नया खरीदना हो. यह नेक काम आप भी कर सकते हैं. आए दिन तरह-तरह के स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच लॉन्च होते हैं. अपने बजट के अनुसार ये गिफ्ट खरीदने का सोच सकते हैं. इयरबड्स भी देना है बेस्ट आइडिया- आजकल इयरबड्स का इस्तेमाल भी लोग खूब करते हैं. यह फायदेमंद भी है, क्योंकि ड्राइव करते समय कान में इसे लगाकर आप किसी से भी फोन पर आराम से बात कर सकते हैं. गाने सुन सकते हैं. गिफ्ट में टेक की चीजें पाकर कोई भी खुश हो जाएगा. साथ ही इन्हें सेलेक्ट करने में भी पसंद-नापसंद वाली समस्या नहीं आती है. हां, बजट जितना हो, उसी के अंदर आप टेक आइटम खरीद कर गिफ्ट करें.
हैंडबैग दें- महिलाओं के पास जितनी वेरायटी के हैंडबैग हों, उतना ही उनके लिए कम होता है. तो क्यों ना आप उनके कलेक्शन में एक और स्टाइलिश डिजाइन का हैंडबैग शामिल कर दें. शॉपिंग मॉल में ढेरों ब्रांडेड बैग्स उचित दामों में उपलब्ध होते हैं. आप चाहें तो ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं.
जूलरी, ड्रेस- महिलाओं को जूलरी और कपड़ों का बेहद शौक होता है. शॉपिंग के लिए जब वे घर से निकलती हैं तो कुछ ना कुछ इनमें से खरीद ही लेती हैं. आपको लग रहा है कि आपके घर में किसी भी लेडी को कपड़ों या जूलरी की जरूर है तो आप जरूर खरीद कर गिफ्ट करें. उनका दिन बन जाएगा.

मंत्री-विधायक सरकारी स्कूलों में बच्चों का करवा रहे एडमिशन
नई स्कूल बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान बोले सीएम केजरीवाल

परिवहन विशेष न्यूज

सीएम केजरीवाल ने पश्चिम विहार के अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस (एएसओएसई) के नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक अपने बच्चों के नाम प्राइवेट स्कूलों से कटवाकर सरकारी में दाखिला करवा रहे हैं। आइडिया अपनाया कि वह सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा कर देंगे कि सभी मंत्री आईएएस अपने बच्चों को वालंटियरली सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू करेंगे।

दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार दोपहर को पश्चिम विहार के अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस (एएसओएसई) के नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी भी उनके साथ रही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मैं स्कूल में घुसा, पहली नजर बिल्डिंग पर पड़ी, तो लगा कि क्या शानदार स्कूल बना है।

केजरीवाल ने बचपन का किया जिक्र

एनसीसी के बच्चों ने प्रोफेशनल तरीके से सलामी दी। इस दौरान अपने बचपन को याद करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि काश मैं भी ऐसे स्कूल में पढ़ा होता। जिस स्कूल से केजरीवाल ने पढ़ाई की, उससे भी बेहतर ये स्कूल है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह हरिणाणा के हिसार का रहने वाले हैं। उन्होंने हिसार के सबसे बेस्ट प्राइवेट स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल भी इतना बेस्ट नहीं था, जितना बेस्ट ये सरकारी स्कूल है।

स्कूल में है 54 क्लासरूम

केजरीवाल ने बताया कि स्कूल में 54 से ज्यादा क्लासरूम हैं, दो बड़ी लाइब्रेरी हैं। 13 से ज्यादा लैबोरेटरी हैं और 18 एक्टिविटी हाल हैं। इतनी शानदार सुविधा दिल्ली के बड़े से बड़े नामी ग्रामी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होंगी। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि दिल्ली के बच्चों को बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं मिले। चाहे कोई गरीब का बच्चा हो या अमीर का, सब को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इस स्कूल में 1200 से ज्यादा बच्चे शिक्षा लें सकेंगे।

देश को याद रखे छात्र

केजरीवाल ने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि वह किसी भी क्षेत्र में जाएं, लेकिन देश को न भूलें, क्योंकि इस देश ने ही उन्हें अच्छी शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि वह आईआईटी खड़कपुर से पढ़े हैं। उन्होंने मकेनिकल इंजीनियरिंग की थी और वर्ष 1989 में पासआउट हुए थे। वहां उन्हें सारी सुविधा मिलती थी। हां की ट्यूशन फीस मात्र 30 रुपये महीना होती थी। उन्होंने कहा कि इतनी कम फीस में कोई नहीं पढ़ सकता।

सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे विधायक

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक अपने बच्चों के नाम प्राइवेट स्कूलों से कटवाकर सरकारी में दाखिला करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वह सरकार में आए तो कुछ लोग उनसे कहते थे कि यह आदेश जारी कर दीजिए कि सभी आईएएस, आईपीएस के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, जबरदस्ती कर दो। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती करने से शिक्षा अच्छी नहीं होती। उन्होंने कहा कि उन्होंने दूसरा आइडिया अपनाया कि वह सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा कर देंगे कि सभी मंत्री, आईएएस अपने बच्चों को वालंटियरली सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू करेंगे।

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी। तब सरकारी स्कूलों के हालात देखकर आंखों में आंसू आ जाते थे। टायलेट से बदबू आती थी।बच्चों के बैठने के लिए डेस्क, कुर्सी नहीं होती थी।शिक्षक की जगह-जगह ड्यूटी लगी होती थी। सरकारी स्कूल के बच्चे हीन भावना से जुझते थे। पिछले नौ वर्ष में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की क्रांति आई है।

संजय सिंह न्यायिक हिरासत से जाएंगे राज्यसभा, शपथ लेने के लिए कोर्ट से फिर मिली अनुमति

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दूसरी बार मंगलवार को संसद जाकर राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी। उन्हें पुलिस हिरासत में 8 फरवरी या 9 फरवरी को संसद जाने की अनुमति दी गई है। कोर्ट के आदेश पर पहले भी उन्हें शपथ दिलाने की अनुमति दी गई थी।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दूसरी बार मंगलवार को संसद जाकर राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी। उन्हें पुलिस हिरासत में 8 फरवरी या 9 फरवरी को संसद जाने की अनुमति दी गई है। कोर्ट के आदेश पर पहले भी उन्हें शपथ दिलाने की अनुमति दी गई थी। उन्हें 5 फरवरी को राज्यसभा में ले जाया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से शपथ नहीं दिलाई जा सकी। इसलिए अब उन्हें शपथ दिलाने की नई तारीखों का एलान किया है।

कुपवाड़ा में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार, पहले सेना में करता था नौकरी

पुलिस टीम ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल का सक्रिय आतंकी को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पुलिस थाने की टीम ने जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से हाल ही में कुपवाड़ा में भंडाफोड़ किए गए आतंकी मॉड्यूल के प्रमुख साजिशकर्ताओं में शामिल एक आंतकी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शख्स की पहचान रियाज अहमद के रूप में हुई है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी रियाज अहमद राथर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

पाकिस्तान में बैठे लश्कर आकाओं के निर्देश पर रियाज अहमद राथर ने एलओसी के पार से हथियार व गोला बारूद प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह पहले सेना में नौकरी करता था। कुछ साल पहले सेवानिवृत्त हो जाने के बाद लश्कर के लिए काम करना शुरू कर दिया था।

डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा के मुताबिक रियाज अहमद राथर मूलरूप से गांव न्यू गबरा, तहसील करनाह ,जिला कुपवाड़ा, जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है। यह लश्कर आकाओं द्वारा एलओसी के पार से हथियार और गोला-बारूद प्राप्त करने में खुर्शीद अहमद राथर और गुलाम सरवर राथर के साथ साजिश रचने में शामिल था।

जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार हुए थे पांच आतंकी

चार फरवरी को जम्मू-कश्मीर पुलिस से नई दिल्ली रेलवे थाना पुलिस को सूचना मिली कि कि रियाज अहमद राथर, हाल ही में जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़े गए आतंकी माड्यूल के सक्रिय सदस्य हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस व सेना की संयुक्त कार्रवाई में पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से पांच एके-47 राइफल, पांच मैग्जीन, 16 कारतूस सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी।

इस संबंध में करनाह थाना पुलिस ने आपराधिक साजिश रचने, भारतीय शस्त्र अधिनियम, 13, 18, 20, 23, 38, 39 व यूएपीए अधिनियम आदि धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था।

इनके कब्जे से बरामद हथियार और गोला-बारूद पीओके स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आका मंजूर अहमद शेख उर्फ शकूर (गबरा करनाह) और काजी मोहम्मद खुशाल (धन्नी करनाह) द्वारा भेजे गए थे। दोनों सीमा पार से ऑपरेट कर रहे थे। इससे पूछताछ में पता चला था कि रियाज अहमद ट्रेन से दिल्ली के लिए गया है।

थानाध्यक्ष विश्वनाथ पासवान, एसआइ नसीब सिंह, एएसआइ यादराम, सुशील,

हवलदार जयवीर और गौरव ने जांच शुरू कर दी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास उसकी लोकेशन का पता चलने पर स्टेशन के प्रवेश व निकास द्वारों पर पुलिस टीमों ने जांच शुरू कर दी।

भीड़ में रियाज अहमद पर नजर पड़ने पर पुलिसकर्मियों ने जब उसे सुबह के समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकास गेट नंबर एक पर पकड़ने की कोशिश की तब वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अलर्ट पुलिस टीम ने उसे वहां से दबोच लिया।

दूसरे ठिकाने भागने की फिराक में था रियाज

पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने दोस्त अल्ताफ के साथ जबलपुर से महाकौशल एक्सप्रेस में सवार हुआ था और तीन फरवरी की दोपहर करीब तीन बजे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा था। वहां से आटो लेकर वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा था। रियाज अहमद राथर किसी दूसरे ठिकाने पर जाने वाला था इससे पहले वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

रियाज अहमद पर खुर्शीद अहमद राथर से हथियार और गोला-बारूद की खेप प्राप्त करने का आरोप है। यूसुफ राथर और गुलाम सरवर राथर को जम्मू-कश्मीर पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। रियाज अहमद और उसका दोस्त अल्ताफ 31 जनवरी 2023 को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

इसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया गया है। रियाज अहमद को कानून की उचित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और जम्मू-कश्मीर के संबंधित थाना पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है।

वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल में अत्याधुनिक नए हेमेटोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नईदिल्ली। भारत के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल में आयोजित एक समारोह में अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ अत्याधुनिक न्यू हेमेटोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी ब्लॉक के उद्घाटन की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) डॉ. अतुल गोयल, डॉ. वंदना तलवार चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. गीतिका खन्ना प्रिंसिपल वीएमएमसी, सभी अतिरिक्त एमएस, एचओडी और ओएनएस और स्टाफ की उपस्थिति में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया।

डॉ. वंदना तलवार ने कहा कि नव स्थापित ब्लॉक कैंसर और हेमटोलॉजिकल विकारों से जूझ रहे

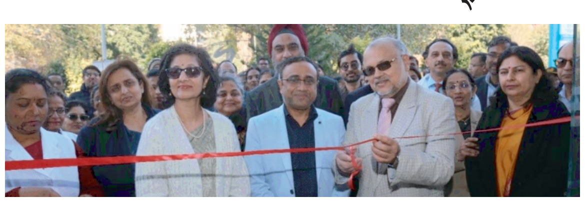

मरीजों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की सफदरजंग अस्पताल की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित और अत्यधिक कुशल चिकित्सा पेशेवरों द्वारा संचालित होगा, इसका उद्देश्य कीमोथेरेपी, सर्जिकल हस्तक्षेप और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण सहित व्यापक देखभाल और उपचार विकल्प प्रदान करना है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग और बीएमटी इकाई के प्रमुख डॉ. कौशल कालरा के अनुसार, इस ब्लॉक में कैंसर रोगियों के लिए विस्तारित गहन देखभाल इकाई (आईसीयू) सुविधाएं भी होंगी। ये संवर्द्धन अपने रोगियों की विविध स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अस्पताल के समर्पण को रेखांकित करते हैं।स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ. अतुल गोयल ने अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि इन अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन समाज के सभी वर्गों को सुलभ, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के सफदरजंग अस्पताल के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

दिल्ली नगर निगम की बैठक में हंगामा, भाजपा पार्षद ने कट मोशन की प्रतियां फाड़कर हवा में लहराई

दिल्ली नगर निगम की बैठक मंगलवार को एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई। मंगलवार को बैठक भाजपा पार्षदों ने आप पार्षदों की ओर से बजट में संशोधन (कट मोशन) के प्रस्तावों को लेकर भाजपा ने विरोध किया। इस दौरान महापौर ने भाजपा पार्षदों को शांत कराने की कोशिश की लेकिन हंगामा शांत होने के लिए पहले सदन की बैठक दस मिनट के लिए स्थगित की।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के संशोधित बजट अनुमान 2023-24 और बजट अनुमान 2024-25 पर चर्चा के लिए बुलाई गई निगम सदन की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। जहां सोमवार को चंडीगढ़ महापौर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर आप और भाजपा पार्षदों में नोंक-झोंक हुई थी तो वहीं मंगलवार को बैठक भाजपा पार्षदों ने आप पार्षदों की ओर से बजट में संशोधन (कट मोशन) के प्रस्तावों को लेकर भाजपा ने विरोध किया।

महापौर के आसन के सामने आए BJP पार्षद

भाजपा पार्षद योगेश वर्मा ने इस सदन में इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद भाजपा पार्षद महापौर डॉ. शैली ओबेराय के आसन के सामने आ गए और महापौर से कट मोशन को वापस लेने की मांग की। इस दौरान महापौर ने भाजपा पार्षदों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन हंगामा शांत होने के लिए पहले सदन की बैठक दस मिनट के लिए स्थगित की। फिर पुनः शुरू हुई बैठक में भाजपा पार्षद महापौर के आसन के समक्ष आ गए।

इसके बाद महापौर ने फिर बैठक को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया। भाजपा पार्षद योगेश वर्मा का कहना है कि चाहे ग्रुप बी के कर्मचारियों के वेतन का मामला हो या वार्ड कमेटियों से लेकर स्थायी समिति, शिक्षा समिति के फंड को महापौर के विवेकाधिकार फंड में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव आप

पार्षदों ने दिया है। वर्मा ने कहा कि यह प्रस्ताव जन विरोधी के साथ ही कर्मचारी विरोधी है।

इन प्रस्तावों का भाजपा विरोध करती हैं। साथ ही इन प्रस्तावों को पास नहीं होने दिया जाएगा। वर्मा ने कहा कि कुल 1500 करोड़ फंड ऐसे मदों से स्थानांरित आप सरकार करना चाहती है जो वैधानिक रूप से ऊचित नहीं है। उल्लेखनीय है कि निगम सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से करीब 49 कटमोशन लगे हुए हैं।

कांग्रेस पार्षदों ने बजट पेश करने पर जताया विरोध

महापौर डा. शैली ओबेराय और कांग्रेस के पार्षदों के बीच निगम सदन की बैठक में नोंक-झोंक हुई। दरअसल, कांग्रेस पार्षद आरिबा खान ने मुद्दा उठाया कि निगमायुक्त ने जो निगम सदन में बजट पेश किया वह निगम एक्ट का उल्लंघन है। जबकि अनुच्छेद 109 के तहत निगम सदन में पेश नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्थायी समति में ही बजट पेश करने का नियम है। उन्होंने कहा कि एक्ट के अनुसार पुरानी जो स्थायी समिति और वार्ड समिति थी उसमें ही निगमायुक्त बजट पेश करते क्योंकि एक्ट के अनुच्छेद 68 में पुरानी कमेटियां भी मान्य होगी जब तक की नई कमेटियों का गठन नहीं हो जाता है।

मौत की झूठी खबर फैलाने के लिए पूनम पांडे को हो सकती है तीन साल की जेल, एक्सपर्ट से जानें क्या कहता है कानून

पूनम पांडे ने सर्वाइकल कैंसर से मौत होने की अफवाह फैलाई जिससे लोग खासा भड़क गए। उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज हुई। सवाल ये है कि जब कोई ट्रेन या फ्लाइट में बम होने की झूठी खबर फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है ऐसे में व या पूनम पांडे पर अपनी ही मौत की झूठी खबर फैलाने के लिए कार्रवाई होगी?

नई दिल्ली। हाल ही में अभिनेत्री पूनम पांडे ने सर्वाइकल कैंसर से मौत होने की अफवाह फैलाई और फिर अगले दिन वीडियो जारी कर कहा कि वह जिंदा हैं। उन्होंने कैंसर अवेयरनेस फैलाने के लिए यह पब्लिसिटी स्टंट किया था। इसके बाद पूनम पांडे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। लोग उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

पूनम पांडे के खिलाफ कार्रवाई की मांग

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पूनम पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे की मौत की फर्जी खबर ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सभी को सदमे में डाल दिया। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए पूनम पांडे के खिलाफ मुंबई पुलिस कार्रवाई करे।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा कि पूनम पांडे ने कैंसर जैसी बीमारी का मजाक बनाया। यह कैंसर पीड़ितों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। पूनम पांडे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

फिल्ममेकर अशोक पंडित ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, "एक्ट्रेस ने कई लोगों के इमोशन्स के साथ खेला है। उन्होंने उन सभी लोगों का भी मजाक उड़ाया जो सर्वाइकल कैंसर से लड़ रहे हैं। मैं सभी गर्वमेंट लॉ एंजेसी से अपील करूंगा कि पूरे देश से झूठ बोलने और यह नाटक रचने के लिए एक्ट्रेस के खिलाफ एक केस दर्ज किया जाए।

क्या बोली मुंबई पुलिस?

मुंबई पुलिस का कहना है कि इस मामले

में लीगल तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

अब सवाल ये है कि जब कोई ट्रेन या फ्लाइट में बम होने की झूठी खबर फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ऐसे में क्या पूनम पांडे पर अपनी ही मौत की झूठी खबर फैलाने के लिए पुलिस कार्रवाई होगी?

क या पूनम पांडे को हो सकती है सजा?

कड़कड़डूमा और तीस हजारी अदालत में प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट मनीष भदौरिया बताते हैं कि पूनम पांडे ने खुद के मरने की झूठी खबर फैलाई। बेशक पूनम का कहना है कि उन्होंने जागरूकता के लिए ऐसा किया, लेकिन उनकी यह हरकत जागरूक करने वाली कम और लोगों के मन में कैंसर को लेकर डर पैदा करने वाली ज्यादा थी।

एडवोकेट मनीष आगे बताते हैं कि जिस वक्त पूनम पांडे के मरने की झूठी खबर सोशल मीडिया पर आई, उस वक्त लोगों के मन में एक डर पैदा हुआ कि कल तक जो अभिनेत्री पार्टी कर रही थी, अचानक उसकी मौत हो गई। मतलब यह लाइलाज बीमारी है।

आईपीसी की धारा 505 में प्रावधान है कि कोई ऐसी अफवाह जिससे लोगों के मन में भय और डर व्याप्त हो जाए, वो कानूनी तौर पर अपराध है। इसके तहत तीन साल तक की जेल की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

सिविल कोर्ट में मांगा जा सकता है मुआवजा

जयपुर हाईकोर्ट के एडवोकेट ऋषि राज सिंह शेखावत के मुताबिक, अगर कोई कैंसर पेशेंट आकर पूनम पांडे के खिलाफ शिकायत कर दें कि अभिनेत्री ने इस गंभीर बीमारी का मजाक बनाया है, जिसके बाद से वह सदमे है। उसे लग रहा है कि कैंसर लाइलाज बीमारी है और अब वह मर ही जाएगा। ऐसी स्थिति में पूनम पांडे पर कार्रवाई हो सकती है।

इसके अलावा, अगर कोई कैंसर पेशेंट यह खबर सुनकर सदमे में चला गया या सुसाइड करने की कोशिश करता है, बाद में वह सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर मुआवजा भी मांग सकता है। नोएडा के एसीपी रजनीश वर्मा कहते हैं कि पूनम पांडे ने जो एक्ट किया, वो अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस का यह तरीका नहीं है। यह क्राइम है। इससे सर्वाइकल कैंसर की दवाओं की कालाबाजारी शुरू हो सकती है।

दिल्ली में फिर चाकूबाजी, वसंत विहार में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर युवक की हत्या

साउथ दिल्ली के वसंत विहार में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात को अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक की पहचान अश्विनी के रूप में हुई है। युवक के शरीर पर कई जगह चाकू से वार किए गए हैं। मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

दक्षिणी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में साउथ दिल्ली के वसंत विहार में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात को अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक, मृतक युवक की पहचान अश्विनी के रूप में हुई है। युवक के शरीर पर कई जगह चाकू से वार किए गए हैं। मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की है। अभी तक आरोपितों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक, सुबह करीब 6 बजे इलाके के कुछ लोगों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वसंत विहार पुलिस थाने की एक टीम मौके पर पहुंची और बताया कि पीड़ित की पहचान अश्विनी (35) के रूप में हुई है। कुछ संदिग्धों को राउंडअप किया गया है। अधिकारी ने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें काम कर रही हैं।

फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड की धारदार हथियार से हत्या, साहिबाबाद गांव के पास मिला शव

लिंक रोड थाना क्षेत्र में साहिबाबाद गांव कट के पास फैक्ट्री के सुरक्षाकर्मी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। अज्ञात कॉलर ने दो व्यक्तियों ने हत्या करने की डायल 112 को सूचना दी थी।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल के पास से पुलिस को मृतक के बैग में कपड़े मिले हैं।

गाजियाबाद। लिंक रोड थाना क्षेत्र में साहिबाबाद गांव कट के पास फैक्ट्री के सुरक्षाकर्मी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। अज्ञात कॉलर ने दो व्यक्तियों ने हत्या करने की डायल 112 को सूचना दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल के पास से पुलिस को मृतक के बैग में कपड़े मिले हैं। पुलिस ने स्वजन को जानकारी दे दी है। मृतक की पहचान भिंड (मुरैना) के देव सिंह (50) के रूप में हुई है। वह औद्योगिक क्षेत्र साइट चार की उत्तम इंजीनियरिंग के नाम से एक फैक्ट्री में काम करते थे। पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने बताया कि चाकू से वार कर हत्या की सूचना पुलिस को मिली थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। स्वजन को जानकारी दे दी है। शिकायत मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। तीन टीमें मामले की जांच में जुटी हैं।

शादियों के सीजन में नोएडा की जनता का बज रहा बैंड, बैंक्वेट हॉल और मैरिज होम में पार्किंग नहीं; जाम से लोग त्रस्त

परिवहन विशेष न्यूज

शहर के 25 बैंक्वेट हॉल सामुदायिक केंद्र मैरिज हॉल लॉन और फार्म हाउस में पार्किंग नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शादी के अलावा अन्य मांगलिक कार्यक्रम के कारण इन मैरिज हॉल के पास नो पार्किंग में वाहन खड़े होने के कारण ट्रैफिक जाम रहता है। शहर में ज्यादातर मैरिज हॉल में पार्किंग व्यवस्था नहीं बनी है।

नोएडा। शहर के 25 बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक केंद्र, मैरिज हॉल, लॉन और फार्म हाउस में पार्किंग नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शादी के अलावा अन्य मांगलिक कार्यक्रम के कारण इन मैरिज हॉल के पास नो पार्किंग में वाहन खड़े होने के कारण ट्रैफिक जाम रहता है।

शहर में ज्यादातर मैरिज हॉल में पार्किंग व्यवस्था नहीं बनी है। सबसे ज्यादा खराब हालात सेक्टर-73 सर्फाबाद से सेक्टर-51 होशियारपुर कट तक के हैं। यहां अधिकांश मैरिज हॉल मुख्य मार्ग पर स्थित हैं। इन दिनों आए दिन शादियों से लेकर सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है।

पार्किंग की नहीं है व्यवस्था

यहां पर वाहनों के खड़ा होने के लिए पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से लोग अपने वाहनों को सड़क पर खड़ा करते है। इससे यहां से गुजरने वाले दूसरे चालकों को परेशानी होती है। वाहन चालक मार्ग पर घंटों जान में फंसते हैं। पिछले दो वर्षों में मैरिज हॉल संचालकों को नोटिस दिया गया था, लेकिन सुधार नहीं हुआ।

नक्से की मंजूरी में ही पार्किंग व्यवस्था

नियम है कि मैरिज होम का नक्शा स्वीकृत होने से पहले ही पार्किंग की व्यवस्था को देखा जाना चाहिए, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न न हो। विनियमित क्षेत्र में जो पार्किंग के मानक निर्धारित हैं, वह मैरिज होम संचालकों पर भी लागू होते हैं।

पार्किंग न होने से ट्रैफिक जाम होना बड़ी समस्या है। इससे बैंड बाजा के इस मौसम में राहगीरों का बैंड बज रहा है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे पार्किंग नहीं होने के बावजूद इनका नक्शा कैसे पास कर दिया गया।

इन मैरिज के हॉल के बाहर स्थिति रहती है खराब

द अवध ग्रीन ग्रेटर नोएडा सिटी पार्क
द हैबिटेट क्लब सिटी पार्क ग्रेटर नोएडा
दा रॉयल हैबिटेट सेंटर सिटी पार्क
ग्राऊंड हैरिटेज रिसार्ट ग्रेटर नोएडा
लांग वुड ग्रीन बैंक्वेट हॉल ग्रेटर नोएडा
तिलपता फार्म हाउस ग्रेटर नोएडा
मिथिल बैंक्वेट हॉल सेक्टर-66 नोएडा
शंकुतत्लय बैंक्वेट हॉल दनकौर
धर्म वाटिका विवाह मंडप, सेक्टर-63 बहलोलपुर
उदयराम नेता जी मैरिज हॉल कासना
आनंदी होम मैरिज हॉल सेक्टर-51
नोएडा वेडिंग विला, सेक्टर-51
रामा बैंक्वेट हॉल होशियारपुर सेक्टर-52
पीके बैंक्वेट सेक्टर-104 नोएडा
विष्णु ग्रीन फार्म हाउस दादरी मार्ग
राजा-रानी फार्म हाउस छपरौला लालकुआं दादरी रोड
भगत पैलेस दादरी-बुलंदशहर रोड
कृष्णा फार्म हाउस दादरी-बुलंदशहर रोड
केएन गार्डन दादरी-बुलंदशहर रोड
मुखिया जी दादरी-लालकुआं रोड
चौधरी हरीओम बैंक्वेट हॉल दादरी-लालकुआं रोड
शुभम फार्म हाउस लालकुआं दादरी रोड मंडी के सामने
सूरज फार्म हाउस दादरी से लालकुआं रोड
टिटानिक फार्म हाउस छपरौला दादरी-लालकुआं रोड
गुलमर्ग गार्डन लालकुआं रोड

नो पार्किंग में वाहन खड़े होने पर कार्रवाई होती है। बैंक्वेट हॉल संचालकों को सड़क पर वाहन नहीं पार्क करने को लेकर नोटिस दिया गया है।

-अनिल यादव, डीसीपी ट्रैफिक, नोएडा

जिस चादर को ओढ़ कर रोज सोता था, उसी से फंदा बना मौत की नींद सो गया अमित

एसएचओ विजयनगर ने बताया कि मृतक की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई है। वह सैटरिंग का काम करता था रात को उसका घर पर विवाद हुआ तो चादर लेकर घर से बाहर निकल गया। घर से कुछ दूरी पर ही स्थित पार्क में उसने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

गाजियाबाद। विजयनगर थाना क्षेत्र के बागू स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क में एक युवक का शव पेड़ पर फंदे पर लटका मिला है। सुबह सैर करने पहुंचे लोगों ने शव को लटका देखा तो मामले की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस का कहना है पारिवारिक विवाद के कारण घर से चादर निकले युवक ने चादर को ही फंदा बनाकर आत्महत्या की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएचओ विजयनगर ने बताया कि मृतक की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई है। वह सैटरिंग का काम करता था, रात को उसका घर पर विवाद हुआ तो चादर लेकर घर से बाहर निकल गया। घर से कुछ दूरी पर ही स्थित पार्क में उसने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। आसपास के लोगों ने बताया कि इसी तरह से छह माह पहले भी एक युवक ने पार्क में फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली थी।

अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 110 एकड़ में कॉलोनी काटने वाले 100 भूमाफिया पर FIR दर्ज

बीते छह माह विभाग ने 150 से अधिक कॉलोनियों पर पीला पंजा चलाया गया और दर्जनों एफआइआर भी दर्ज की गई। इसी कड़ी में अब विभाग की तरफ से जनवरी माह में की गई सिफारिश पर करीब 15 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 100 से अधिक जमीन मालिकों को नामजद किया गया है। यह कॉलोनियों करीब 110 एकड़ में काटी जा रही थी।

गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट (डीटीपीई) की सिफारिश पर सोहना, मानेसर, पटौदी, फरुखनगर में कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने को लेकर 100 से अधिक जमीन मालिकों के विरुद्ध सुशांत लोक टू सेक्टर-56 स्थित एन्फोर्समेंट थाने में 15 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। जनवरी माह में डीटीपीई की तरफ से इन मामलों को दर्ज करने के लिए सिफारिश की गई थी जिसके बाद एन्फोर्समेंट थाने में मामले दर्ज किए गए हैं।

150 से अधिक कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

एन्फोर्समेंट टीम की तरफ से सोहना, मानेसर, फरुखनगर, पटौदी में अवैध कालोनियों के विरुद्ध लगातार तोड़फोड़ कार्रवाई जारी है। बीते छह माह विभाग ने 150 से अधिक कॉलोनियों पर पीला पंजा चलाया गया और दर्जनों एफआइआर भी दर्ज की गई। इसी कड़ी में अब विभाग की तरफ से जनवरी माह में की गई सिफारिश पर करीब 15 मामले दर्ज किए गए हैं।

110 एकड़ में काटी जा रही थी अवैध कॉलोनी

इनमें सोहना-भोंडसी में तीन, मानेसर के बिलासपुर, भोड़ाकलां में तीन, फरुखनगर में छह, पटौदी में तीन अवैध कॉलोनियों समेत कुल 15 मामले दर्ज कराए गए हैं। इनमें 100 से अधिक जमीन मालिकों को नामजद किया गया है और कुछ प्रॉपर्टी डीलर भी शामिल हैं। यह कॉलोनियों करीब 110 एकड़ में काटी जा रही थी। विभाग की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने से पहले कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा गया था, जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो रिस्टोरेशन के आदेश दिए गए।

जमीन मालिकों के खिलाफ 15 FIR दर्ज

जमीन को रिस्टोर करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया, लेकिन जब रिस्टोर नहीं की तो तोड़फोड़ कार्रवाई की गई। इन सभी कॉलोनियों में विभाग की तरफ से एक से दो बार तोड़फोड़ कार्रवाई की गई है। इसके बाद भी जब जमीन मालिक नहीं माने तो एन्फोर्समेंट टीम की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट के तहत कृषि भूमि जमीन पर बिना टाउन प्लानिंग विभाग की परमिशन के कॉलोनी नहीं काटी जा सकती है। इसके बावजूद जमीन मालिक और प्रॉपर्टी डीलर मिलकर कॉलोनी काट रहे हैं। विभाग की तरफ से जनवरी माह में अवैध कॉलोनियां काटने पर अलग-अलग इलाकों के जमीन मालिकों के विरुद्ध 15 मामले दर्ज कराए गए हैं। जनवरी माह में एन्फोर्समेंट थाने में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई थी।

महिला किसानों को मिलेगा सहयोग, महंगाई पर जताई नाराजगी

इससे जिले में बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थियों को लाभ मिल सकेंगे। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा भी रसोई के सामान पर विशेष सब्सिडी न देने पर नाराजगी भी जताई। बजट में सुमंगला योजना के अंतर्गत बालिकाओं के लिए छह श्रेणियों में मिले लाभ मिलने एवं महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है।

गाजियाबाद। बजट को लेकर महिलाओं को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। इस साल निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर एक हजार रुपये प्रतिमाह कर दी गई।

इससे जिले में बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थियों को लाभ मिल सकेंगे। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा भी रसोई के सामान पर विशेष सब्सिडी न देने पर नाराजगी भी जताई।

बजट में सुमंगला योजना के अंतर्गत बालिकाओं के लिए छह श्रेणियों में मिले लाभ मिलने एवं महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है।

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ति महिलाओं एवं बालिकाओं को कोष के अंतर्गत एक लाख रुपये से 10 लाख रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था पर जिक्र बजट में किया।

निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की धनराशि बढ़ाने से जिले में भी बड़ी संख्या में महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। महिला किसान सशक्तिकरण के लिए भी बजट में हिस्सा दिया गया है।

- नीतू चौधरी

लगातार रसोई के सामान पर महंगाई बढ़ रही है। महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार दोनों ओर से ही बजट में ध्यान नहीं दिया।

- ममता सिंह

यूसीसी पर उत्तराखंड ने जो सार्थक पहल की है उससे दूसरे राज्यों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए

ललित गर्ग

आज जबकि भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, जी-20 देशों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत कर चुका है, भारत की अहिंसा एवं योग को दुनिया ने स्वीकारा है, विश्व योग दिवस एवं विश्व अहिंसा दिवस जैसे आयोजनों की संरचना हुई है।

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान आचार संहिता (यूसीसी) के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी और इसे विधानसभा में पेश भी कर दिया। अब चार दिनों के विशेष सत्र में इसे आसानी से पारित भी कर दिया जायेगा। इस तरह देश को आजादी मिलने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। इससे पहले गोवा में यह लागू है। आजादी के अमृतकाल में समानता की स्थापना के लिये इससे अपूर्व वातावरण निर्मित होगा। यह उत्तराखण्ड ही नहीं, समूचे भारत की बड़ी जरूरत है। समानता एक सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक लोकतांत्रिक मूल्य है। इस मूल्य की प्रतिष्ठापना के लिये समान कानून की अपेक्षा है। यूसीसी देश की राजनीति के सबसे विवादित मुद्दों में रहा है। हालांकि संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों के रूप में इसका उल्लेख है। इस लिहाज से राजनीति की सभी धाराएं इस बात पर एकमत रही हैं कि देश में सभी पंथों, आस्थाओं से जुड़े लोगों पर एक ही तरह के कानून लागू होने चाहिए। राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति, वर्ग, सम्प्रदाय, जाति जब-तक कानूनी प्रावधानों के भेदभाव को झेलेगा, तब तक राष्ट्रीय एकता, एक राष्ट्र की चेतना जागरण का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। उत्तराखण्ड एवं गोवा के बाद असम और गुजरात जैसे राज्य भी समान आचार संहिता को लागू करने की तैयारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी एवं नरेन्द्र मोदी सरकार यूसीसी लागू करने की मांग जोरदार तरीके से करती आ रही है और इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाया है। भारतीय न्यायपालिका की तरफ से भी बार-बार इसे लागू करने की जरूरत बताई जा रही है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि देश में इसे लेकर जागरूकता हाल के दिनों में बढ़ी है और इसका श्रेय भाजपा को दिया जाना चाहिए।

समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत देश के सभी धर्मों, पंथों और समुदायों के लोगों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था का प्रस्ताव है। भारत के विधि आयोग ने राजनीतिक रूप से अतिसंवेदनशील इस मुद्दे पर देश के तमाम धार्मिक संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए थे। यूसीसी में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, उत्तराधिकार, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एकसमान कानून बनाया जाना है। पिछले कुछ समय से इस पर अच्छी खासी बहस चली है। लिहाजा एक-एक करके अलग-अलग राज्यों में इसे लागू करने और वहां के अनुभव के आधार पर आगे बढ़ने का ख्याल गलत नहीं कहा जा सकता। उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तराखण्ड विधानसभा में इसे पेश किए जाने और वहां बहस शुरू होने के बाद इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर रोशनी पड़ेगी और सभी दुविधाएं, शंकाएं एवं संदेह दूर हो जाएंगे। जो अन्य राज्यों के लिये लागू करने का आधार बनेगी।

भारतीय संविधान के मुताबिक भारत एक धर्म-निरपेक्ष देश है, जिसमें सभी धर्मों व संप्रदायों (जैसे- हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, आदि) को मानने वालों को अपने-अपने धर्म से सम्बन्धित कानून बनाने का अधिकार है। भारत में दो प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1956 जो कि हिंदू, सिख, जैन व अन्य संप्रदायों पर लागू होता है। दूसरा, मुस्लिम धर्म को मानने वालों के लिए लागू होने वाला

मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में जबकि मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों व संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है तो मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लागू होने की बात की जा रही है, जो प्रासंगिक होने के साथ नये बन रहे भारत की अपेक्षा है। अभी मीडिया में छन-छन कर जो सूचनाएं आ रही हैं, उनके मुताबिक शादी, तलाक, अडॉप्शन से जुड़े कानूनों में एकरूपता के जो प्रावधान हैं, वे यूसीसी की मूल अवधारणा के अनुरूप ही हैं। बहरहाल, उत्तराखण्ड राज्य सरकार की यह एक बड़ी पहल है और इस पर अमल की प्रक्रिया ही नहीं, इसके नतीजों पर भी पूरे देश की नजरें रहेंगी।

आज जबकि भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, जी-20 देशों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत कर चुका है, भारत की अहिंसा एवं योग को दुनिया ने स्वीकारा है, विश्व योग दिवस एवं विश्व अहिंसा दिवस जैसे आयोजनों की संरचना हुई है। इन सब सकारात्मक स्थितियों को देखते हुए भारत की कानून विषयक विसंगतियों को दूर करना अपेक्षित है। क्योंकि विश्व के कई देशों में समान नागरिक संहिता का पालन होता है। इन देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्किये, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका, आयरलैंड, आदि शामिल हैं। इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए एकसमान कानून है और किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग कानून नहीं हैं। लेकिन भारत में राजनीतिक फायदे के लिए तुष्टिकरण का ऐसा खेल खेला गया, जो विविधता में एकता एवं वसुधैव कुटुम्बकम के दर्शन को तार-तार कर रहा है। निजी कानूनों के कारण कहीं-कहीं विसंगति के हालात भी पैदा हो रहे हैं। सामुदायिक घटनाओं को भी राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता है, घटना को देखने का यह नजरिया वास्तव में वर्ग भेद को बढ़ावा देने वाला है।

देश का मुस्लिम भी समाज का एक हिस्सा है, जिसे इसी रूप में प्रस्तुत करने की परिपाटी चलन में आ जाए तो भेद करने वाले विचारों पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन हमारे देश के कुछ राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को ऐसे भ्रम में रखने के लिए प्रेरित किया कि वह भी ऐसा ही चिंतन करने लगा, जबकि सच्चाई यह है कि आज के मुसलमान बाहर से नहीं आए, वे भारत के ही हैं। परिस्थितियों के चलते उनके पूर्वज मुसलमान बन गए। वे सभी स्वभाव से आज भी भारतीय हैं और विचार से सनातनी हैं, लेकिन देश के राजनैतिक दल अपने राजनीतिक लाभ एवं वोट बैंक के चलते मुसलमानों के इस सनातनी भाव को प्रकट करने का अवसर नहीं दे रहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ में अनेक विसंगतियां हैं, जैसे शादीशुदा मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को महज तीन बार तलाक कहकर तलाक दे सकता था। इसके दुरुपयोग के चलते सरकार ने इसके खिलाफ कानून बनाकर जुलाई 2019 में इसे खत्म कर दिया है। तीन तलाक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि सदियों से तीन तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला है।

वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग समान नागरिक कानून का विरोध कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम समाज की महिलाएं इस कानून के समर्थन करने के लिए आगे आ रही हैं। 1985 में शाहबानो केस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला सुर्खियों में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद शाहबानो के पूर्व पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संसद में बिल पास कराया था। इस कानून के समर्थकों का मानना है कि अलग-अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। अगर हम यह चिंतन भारतीय भाव से करेंगे तो स्वाभाविक रूप से यही दिखाई देगा कि समान नागरिक कानून देश और समाज के विकास का महत्वपूर्ण आधार बनेगा।

एथर एनर्जी फैमिली ई-स्कूटर पर कर रही है काम, कंपनी ने टीज की तस्वीर

Ather Energy वर्तमान में भारतीय बाजार के लिए एक फैमिली ई-स्कूटर पर काम कर रही है। बेंगलुरु स्थिति इस स्टार्ट-अप ने हाल ही में Rizta नाम के इस Electric Scooter का टीजर साझा किया है। उम्मीद है कि Ather Rizta को आने वाले महीनों में पेश किया जाएगा। इसके तुरंत बाद इसकी लॉन्चिंग और कीमत की घोषणा की जाएगी संभवत: 2024 के मध्य तक ये प्रक्रिया पूरी होगी।

नई दिल्ली। Ather Energy वर्तमान में भारतीय बाजार के लिए एक फैमिली ई-स्कूटर पर काम कर रही है। बेंगलुरु स्थिति इस स्टार्ट-अप ने हाल ही में Rizta नाम के इस Electric Scooter का टीजर साझा किया है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा Rizta नाम को भी ट्रेडमार्क किया गया था, साथ ही यह पुष्टि की गई थी कि ये फैमिली स्कूटर अगले 6 महीनों में भारतीय सड़कों पर चलना शुरू कर देगा।

Ather Rizta में क्या खास?

उम्मीद है कि Ather Rizta को आने वाले महीनों में पेश किया जाएगा। इसके तुरंत बाद इसकी लॉन्चिंग और कीमत की घोषणा की जाएगी, संभवतः 2024 के मध्य तक ये प्रक्रिया पूरी होगी। इस फैमिली ई-स्कूटर के टेस्टिंग प्रोटोटाइप को बेंगलुरु के आसपास परीक्षण करते हुए देखा गया है, जिससे इसके डिजाइन के बारे में नए विवरण सामने आए हैं।

कंपनी के CEO ने किया ये खुलासा

Ather Energy के सीईओ ने ब्रांड के आगामी ई-स्कूटर रिज्टा के सीट आकार की तुलना सेगमेंट के सबसे ज्यादा बिकने वाले Ola S1 Pro से करते हुए एक टीजर साझा किया है। इसके अलावा, एक अन्य वीडियो में उन्हें होंडा एक्टिवा और एथर रिज्टा की सीटों की अगल-बगल तुलना करते देखा गया। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एथर अपने आगामी फैमिली ओरिएंटेड ई-स्कूटर के साथ स्पेस और व्यावहारिकता पर बड़ा दावा कर रहा है।

जहां तक स्पाई शॉट्स का सवाल है, आप इसके बड़े आकार को आसानी से देख सकते हैं और ये Athe के 450X लाइनअप की तुलना में डायमेंशन के मामले में अपेक्षाकृत बड़ा लगता है। ये इस तथ्य से उचित है कि यह एक फैमिली-ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, जिसमें यूटिलिटी और व्यावहारिकता सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इसके अलावा, ई-स्कूटर पर अच्छा सामान इस बात पर प्रकाश डालता है कि ये लोड टेस्टिंग से गुजर रहा है। पूर्ण लोड के साथ ई-स्कूटर का परीक्षण करना काफी जरूरी बन जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पारिवारिक उपयोग पर लक्षित है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

उम्मीद है कि रिज्टा में ऑल एलईडी लाइट्स, राइडिंग मोड्स, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फास्ट चार्जिंग और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं। हार्डवेयर यूनिट में, ई-स्कूटर में दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक और पारंपरिक सस्पेंशन सेटअप के साथ 12-इंच के अलाय व्हील दिए गए हैं। इसकी बैटरी और पावरट्रेन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

भारतीय बाजार जल्द लॉन्च होंगे ये 3 नए टू-व्हीलर्स, लिस्ट में एक EV भी शामिल

शक्तिशाली 440cc इंजन से लैस एक रेट्रो-आधुनिक क्रूजर Mavrick 440 लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसे हार्ले-डेविडसन X440 के समान प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जिसमें समान इंजन भी है। काइनेटिक ग्रीन ई-लूना के साथ प्रतिष्ठित लूना मोपेड को इलेक्ट्रिक अवतार में पुनर्जीवित कर रहा है। अपने पूर्ववर्ती के व्यावहारिक डिजाइन को बरकरार रखते हुए ये इलेक्ट्रिक मोपेड सादगी और एफिशियंशी का वादा करता है।

नई दिल्ली। देश की टू-व्हीलर ऑटो इंडस्ट्री के अंदर कई नए लॉन्च होने वाले हैं। देश की पॉपुलर दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा आने निकट भविष्य में कई 2Wheelers लॉन्च किए जाएंगे। अपने इस लेख में हम आपके लिए टॉप-3 टू-व्हीलर्स की लिस्ट लेकर आए हैं। आइए, इनके बारे में जान लेते हैं।

Kinetic E-Luna

काइनेटिक ग्रीन ई-लूना के साथ प्रतिष्ठित लूना मोपेड को इलेक्ट्रिक अवतार में पुनर्जीवित कर रहा है। अपने पूर्ववर्ती के व्यावहारिक डिजाइन को बरकरार रखते हुए, ये इलेक्ट्रिक मोपेड सादगी और एफिशियंशी का वादा करता है।
ये 100 किमी तक की प्रभावशाली रेंज का वादा करता है, लेकिन अधिकतम गति केवल 50 किमी प्रति घंटे है। सिर्फ 500 रुपये में इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो गई है और इसके आने वाले दिनों में लॉन्च होने की उम्मीद है।

Hero Mavric 440

Hero MotoCorpशक्तिशाली 440cc इंजन से लैस एक रेट्रो-आधुनिक क्रूजर Mavrick 440 लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसे हार्ले-डेविडसन X440 के समान प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसमें समान इंजन भी है। हालांकि, इस इंजन को थोड़ा अलग तरह से ट्यून किया गया है।
एलईडी लाइटिंग और एक मजबूत फ्यूल टैंक व विशिष्ट डिजाइन के Hero Mavric स्टाइल और परफॉरमेंस का मिश्रण नजर आती है। इसकी लॉन्चिंग अप्रैल 2024 में तय की गई है और इसकी कीमत इसके हार्ले-डेविडसन समकक्ष से कम होने की उम्मीद है।

Suzuki V-Strom 800 DE

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने हाल ही में भारत मोबिलिटी एक्सपो में Suzuki V-Strom 800 DE पेश की है। इसके 2024 के मध्य में लॉन्च होने की उम्मीद है। ये मिडिलवेट एडवेंचर बाइक अपनी मजबूत चेसिस और शक्तिशाली 776cc इंजन की बदौलत शहर की सड़कों और ऑफ-रोड इलाके दोनों के लिए बेहतर साबित होने वाली है। प्रभावशाली प्रदर्शन देने के अलावा, ये सुजुकी ADV बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ड्राइव मोड सिलेक्ट्र, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और टू-लेवल ABS जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आएगी।

एसयूवी कॉउप क्या होती हैं? यहां देखिए अपकमिंग कूप एसयूवी की लिस्ट

Coupe SUV एक स्पोर्ट यूटिलिटी वाहन है जिसमें फास्टबैक के समान ढलान वाली पिछली छत होती है। ढलान वाली छत का उपयोग इसके नियमित एसयूवी सिब्लिंग की तुलना में स्टाइलिंग लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। टाटा कर्व में एक यूनिट नॉचबैक आकार है जो हाई-राइडिंग एटीट्यूड वाली सेडान जैसा दिखता है। आइए अन्य कूप-एसयूवी के बारे में बी जान लेते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग नए युग की तकनीक और खरीदारों के साथ विकसित हो रहा है। जहां नए जमाने की तकनीक कई युवा कार ग्राहकों को लुभाती है, वहीं फैंसी बॉडी फॉर्म भी नई पहचान बना रही है। अपने इस लेख में हम आपके लिए मौजूदा समय में ट्रेंड कर रहे कूप-एसयूवी सेगमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए, इस सेगमें की अपकमिंग कारों के साथ-साथ जान लेते हैं कि आखिर कूप-एसयूवी होती क्या हैं?

SUV coupe या coupe SUV क्या होती हैं?

Coupe SUV एक स्पोर्ट यूटिलिटी वाहन है, जिसमें फास्टबैक के समान ढलान वाली पिछली छत होती है। ढलान वाली छत का उपयोग इसके नियमित एसयूवी सिब्लिंग की तुलना में स्टाइलिंग लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक एसयूवी की तुलना में इन कारों को अक्सर प्रीमियम विकल्प के रूप में देखा जाता है। आइए, अपकमिंग SUV coupe के बारे में जान लेते हैं।

Tata Curvv

टाटा कर्व में एक यूनिट नॉचबैक आकार है, जो हाई-राइडिंग एटीट्यूड वाली सेडान जैसा दिखता है। इस कूप-एसयूवी में एलईडी हेडलाइट्स के लिए ट्रायंगुलर हाउसिंग के साथ एक माचो बोनट डिजाइन है। फ्रंट ग्रिल नई लॉन्च की गई हैरियर और सफारी से प्रभावित है और एक एलईडी बार बोनट की लंबाई तक जाता है।

Citroen C3X

Citroen C3X ऑटोमेकर का पांचवां प्रोडक्ट होगा और इसमें एसयूवी जैसा लुक होगा। इसके मौजूदा स्पाई शॉट्स बाहरी हिस्से के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं करती हैं। सामने का भाग C3 एयरक्रॉस जैसा दिखता है। साइड और रियर प्रोफाइल के बारे में बहुत कम विवरण हैं, क्योंकि वे काफी हद तक छिपे हुए थे।

Toyota की Frox आधारित कूप-एसयूवी

टोयोटा-आधारित फ्रोंक्स एक अन्य प्रमुख एसयूवी कूप है, जो इस वर्ष पेश की जाएगी। माना जा रही है कि इस चार पहिया वाहन का डिजाइन मारुति सुजुकी फ्रोंक्स जैसा ही होगा। हालांकि, आगे और पीछे महत्वपूर्ण बदलाव की भविष्यवाणी की गई है।

मारुति फ्रॉन्क्स का टर्बो वेलोसिटी एडिशन हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और खासियत

Maruti Suzuki Fronx के Turbo Velocity एडिशन को यांत्रिक रूप से अपरिवर्तित रखा गया है। नए संस्करण में अब कई बाहरी और आंतरिक बदलाव किए गए हैं। पैकेज में कुल 16 एक्सटीरियर और इंटीरियर एक्सेसरीज शामिल हैं। फ्रोंक्स को दो परिचित इंजन विकल्प मिलते हैं जिनमें 89 एचपी और 113 एनएम टॉर्क देने वाला 1.2-लीटर पेट्रोल मोटर शामिल है। ये 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड एएमटी ट्रांसमिशन से जुड़ा है।

नई दिल्ली। Maruti Suzuki ने Fronx को Turbo Velocity एडिशन में लॉन्च किया है। कंपनी ने मॉडल लाइनअप का और विस्तार किया है, जो हाल ही में भारत में सबसे तेजी से 1 लाख बिक्री वाली कार बन गई है। डेल्टा+, जेटा या अल्फा वेरिएंट चुनने पर टर्बो वेलोसिटी एडिशन को अतिरिक्त 43,000 रुपये में खरीदा जा सकता है। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

Turbo Velocity एडिशन में क्या नया?

Maruti Suzuki Fronx के Turbo Velocity एडिशन को यांत्रिक रूप से अपरिवर्तित रखा गया है। नए संस्करण में अब कई बाहरी और आंतरिक बदलाव किए गए हैं। पैकेज में कुल 16 एक्सटीरियर और इंटीरियर एक्सेसरीज शामिल हैं।
इसमें एक ग्रे और काले रंग की एक्सटीरियर स्टाइलिंग किट, डोर वाइजर, ओआरवीएम कवर, हेडलैंप गार्निश, बॉडी साइड मोल्डिंग, इल्यूमिनेटेड डोर सिल गार्ड, रेड डैश-डिजाइन वाली मैट, 3डी बूट मैट, स्पॉइलर एक्सटेंडर, व्हील आर्च गार्निश, फ्रंट ग्रिल गार्निश और कार्बन फिनिश के साथ एक इंटीरियर स्टाइलिंग किट शामिल है।

इंजन ऑप्शन

फ्रोंक्स को दो परिचित इंजन विकल्प मिलते हैं, जिनमें 89 एचपी और 113 एनएम टॉर्क देने वाला 1.2-लीटर पेट्रोल मोटर शामिल है। ये 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड एएमटी ट्रांसमिशन से जुड़ा है।
इसके अतिरिक्त 99 एचपी और 148 एनएम टॉर्क पैदा करने वाली 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल यूनिट है, जो 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प के साथ उपलब्ध है। विशेष रूप से, टर्बो वेलोसिटी संस्करण केवल टर्बो-पेट्रोल यूनिट के साथ जोड़ा गया है।

2024 ह्युंडई क्रेटा को एक महीने के अंदर मिली 51 हजार से ज्यादा बुकिंग, जानिए कीमत और खासियत

Hyundai Creta Facelift की कीमत की घोषणा के एक सप्ताह से भी कम समय में हुंडई ने 51000 बुकिंग के आंकड़े को पार कर लिया है। इसके एक्सटीरियर डिजाइन को नया रूप दिया गया है जबकि इंटीरियर में अपने पूर्ववर्ती की तुलना में प्रीमियम क्वालिटी के मामले में उल्लेखनीय बदलाव किए गए हैं। 2024 Hyundai Creta कुल 7 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। 2024 कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से हुंडई ने Creta Facelift के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। इसके ठीक एक महीने बाद 2024 क्रेटा की आधिकारिक कीमतों की घोषणा की गई। इस प्रकार, कीमत की घोषणा के एक सप्ताह से भी कम समय में हुंडई ने 51,000 बुकिंग के आंकड़े को पार कर लिया है।

कीमत और खासियत

नई Hyundai Creta की शुरुआती कीमत 10.99 लाख रुपये है और ये 19.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है। मध्यम आकार की एसयूवी ने समय के साथ अपनी श्रेणी में अपना प्रभुत्व बनाए रखा है और हालिया फेसलिफ्ट दूसरी पीढ़ी की क्रेटा के चल रहे विकास में एक महत्वपूर्ण अपडेट का प्रतीक है, जिसने 2020 में अपनी शुरुआत की थी।

डिजाइन

इसके एक्सटीरियर डिजाइन को नया रूप दिया गया है, जबकि इंटीरियर में अपने पूर्ववर्ती की तुलना में प्रीमियम क्वालिटी के मामले में उल्लेखनीय बदलाव किए गए हैं। फीचर्स के मामले में भी महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं और लाइनअप में एक नया 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन पेश किया गया है । ये पावरट्रेन 160 पीएस की शक्ति और 253 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है। इसे 7-स्पीड डीसीटी के साथ जोड़ा गया है।

वेरिएंट

2024 Hyundai Creta कुल 7 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है। इसमें ई, ईएक्स, एस, एस (ओ), एसएक्स, एसएक्स टेक और एसएक्स (ओ) शामिल है। इसके रंग विकल्पों में 6 सिंगल-टोन शेड्स और एक टू-टोन शेड का चयन शामिल है। लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) तकनीक का आगमन एक महत्वपूर्ण आकर्षण के रूप में सामने आया है, जो कुल 19 सहायक और सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करता है।

फीचर्स

अपडेटेड इक्विपमेंट लिस्ट में एक नया 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक नया 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6 एयरबैग, वॉइस- इनेबल्ड पैनोरमिक सनरूफ, 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टीपीएमएस, लेदरेट डी-कट स्टीयरिंग व्हील और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स सहित कई बड़े बदलाव किए गए हैं।

इंजन

नियमित 1.5 लीटर NA पेट्रोल इंजन 115 पीएस और 144 एनएम उत्पन्न करता है, जबकि 1.5 लीटर डीजल 116 पीएस और 250 एनएम उत्पन्न करता है। इसके लिए 6-स्पीड एमटी, आईवीटी, छह-स्पीड एटी और 7-स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन विकल्प हैं।

चुनावी साल का संयमित बजट

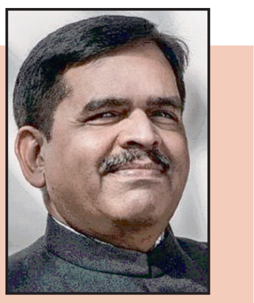

डा. अश्विनी महाजन

अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार का अनुमान है कि यह घाटा 5.1 प्रतिशत रहेगा। विपक्ष का आरोप था कि सरकार कर्ज का बोझ बढ़ा रही है, लेकिन अंतरिम बजट में कर्ज की सीमा 14.1 लाख करोड़ रुपए रखी गई है। जो कुल उधार है, वह 11.74 लाख करोड़ रुपए ही है। इसका अर्थ यह है कि इस वर्ष सरकार पिछले साल से भी कम कर्ज लेगी। होता यह है कि हर साल कर्ज बढ़ता रहता है। इस बार अभूतपूर्व है कि यह जीडीपी के अनुपात में कम हो रहा है।

समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार का कर्ज, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में और घटेगा और रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग को बढ़ा सकती हैं। इसका असर यह हो सकता है कि निवेशक भारत में और अधिक आकर्षित होंगे। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अंतरिम बजट की मर्यादा रखते हुए वित्त मंत्री ने राजकोषीय संयम को दर्शाते हुए सरकार की कल्याणकारी और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला दस्तावेज पेश किया है'

हालांकि फरवरी 1, 2024 को संसद में प्रस्तुत एक अंतरिम बजट ही था, लेकिन आने वाले आम चुनावों में मात्र कुछ माह ही बचे हैं, इसलिए यह अपेक्षा की जा रही थी कि इस बजट में कुछ लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा हो सकती है। साथ ही साथ कुछ लोग मान रहे थे कि आयकर में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसी सभी संभावनाओं को नकारते हुए, अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री ने न केवल राजकोषीय संयम और विवेक का परिचय दिया है, बल्कि बजट के इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए, उन्होंने मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के कामकाज का लेखा-जोखा तो दिया ही, अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी बताया। राजकोषीय घाटा और भी घटा : पिछले बजट में राजकोषीय घाटा के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) के अनुपात में 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया था। ऐसा माना जा रहा था कि चूंकि इस वर्ष नॉमिनल जीडीपी कम रहेगी, इसलिए वित्तीय घाटा अनुमान से भी अधिक हो सकता है। लेकिन हुआ यह कि संशोधित अनुमानों में यह घाटा 5.8 प्रतिशत रहने की आशा बजट में की गई है। इससे इंगित होता है कि सरकार ने वित्तीय विवेक का उपयोग करते हुए घाटे को कम रखने का प्रयास किया है। इसका कारण यह है कि सरकार के पास राजस्व पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। देश में जो आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं, उसके कारण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट आयकर आदि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सरकार का अनुमान था कि राजस्व वृद्धि की दर 10.7 प्रतिशत रहेगी, लेकिन यह वृद्धि दर 15 प्रतिशत रही है। इस बढ़ोतरी के कारण खर्च बढने के बावजूद वित्तीय घाटा कम रहा है।

अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार का अनुमान है कि यह घाटा 5.1 प्रतिशत रहेगा। विपक्ष का आरोप था कि सरकार कर्ज का बोझ बढ़ा रही है, लेकिन अंतरिम बजट में कर्ज की सीमा 14.1 लाख करोड़ रुपए रखी गई है। जो कुल उधार है, वह 11.74 लाख करोड़ रुपए ही है। इसका अर्थ यह है कि इस वर्ष सरकार पिछले साल से भी कम कर्ज लेगी। होता यह है कि हर साल कर्ज बढ़ता रहता है। इस बार अभूतपूर्व है कि यह जीडीपी के अनुपात में कम हो रहा है। गौरतलब है कि कर्ज में कमी से महंगाई की आशंका भी कम होती है। वित्तीय घाटा और महंगाई एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस पर भी सरकार ने समुचित ध्यान रखा है। कुल मिलाकर, जो वित्तीय प्रबंधन है, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन है, उस दृष्टि से यह जो अंतरिम बजट है, उसे कोई भी, विपक्ष भी नहीं कह सकता है कि यह एक लोकलुभावन बजट है, जो चुनावी लाभ की दृष्टि से लाया गया है। इस बात में कोई शंका नहीं कि इन सालों में देश और दुनिया के समक्ष सबसे बुरी महामारी तो देखी ही, युद्ध और तनाव की स्थितियों के कारण ग्लोबल वैल्यू चेन के ध्वस्त होने के बावजूद इस सरकार ने अत्यंत बेहतर तरीके से अर्थव्यवस्था का संचालन किया है। 2014 में दुनिया की पांच सर्वाधिक जर्जर अर्थव्यवस्थाओं में से एक से निकालकर भारत को दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाने का काम इस सरकार ने किया है। 2020-21 के ऋणात्मक जीडीपी संवृद्धि से बाहर निकालते हुए दुनिया की सर्वाधिक संवृद्धि दर तक लाने का श्रेय भी इस सरकार को जाता है। अर्थव्यवस्था के तमाम आयामों प्रौद्योगिकी, उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र सभी में भारत आगे बढ़ा है। पिछले 4 वर्षों में लगातार पूंजीगत खर्च बढ़ाया गया है और इस साल भी उसे जारी रखा गया है और इस बार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11.11 लाख करोड़ के खर्च का प्रावधान रखा गया है। लोक कल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण), हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना, सभी को बिजली, शौचालय समेत कई अन्य योजनाओं को लागू किया गया। इस अंतरिम बजट में भी इसे आगे बढ़ाया गया है। 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों के निर्माण, 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का कार्यक्रम तो पहले से चल रहे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम तो हुआ ही है, एक करोड़ लोगों को रूफ टॉप सोलर के माध्यम से मुफ्त बिजली देने का प्रावधान, मुफ्त की बिजली उपलब्ध करवाने वाले राज्यों को एक सबक भी है, जिसमें सोलर बिजली के उत्पादन के माध्यम से मुफ्त बिजली का प्रावधान है।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि, जिसके माध्यम से सडक़, रेल और अन्य प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। समझना होगा कि सडक़, रेल, जल, वायु यातायात इंफ्रास्ट्रक्चर आदि सभी हमारी लॉजिस्टिक लागत को कम करता है जिससे हमारी प्रतिस्पद्र्धा शक्ति बढ़ती है, जिससे हमारे निर्यात बढ़ते हैं और आयात कम होते हैं।

रूफ टॉप सोलर के जरिए एक करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली देने का प्रावधान : अंतरिम बजट के माध्यम से सरकार ने मुफ्त बिजली देने वालों के लिए एक नई दिशा देने का भी प्रयास किया है। कई सरकारें मुफ्त बिजली देने की तरह-तरह योजनाएं चला रही हैं। इस संबंध में यह सोचने की आवश्यकता है कि इस तरह की फ्रीबीज को बांटने के लिए धन कहां से आएगा। तो, यह प्रस्तावित किया गया है कि मुफ्त बिजली उन लोगों को दी जानी चाहिए जो अपने घरों पर सोलर पैनल लगाएं। इस प्रकार वे बिजली भी पैदा करेंगे और मुफ्त में बिजली भी हासिल करेंगे। ऐसे प्रयास से देश में स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन भी बढ़ेगा और लोगों को निःशुल्क बिजली भी मिलने लगेगी। हालांकि बजट प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं है, पर अगर सरकार को सौर ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भी देती है, तो वह लाभकारी होगा क्योंकि उसका फायदा 25-30 साल तक मुफ्त बिजली के रूप में मिलता रहेगा। ऐसी सब्सिडी दरअसल भविष्य के लिए एक निवेश साबित होगी। यह एक नई दिशा है। यह उम्मीद करनी चाहिए कि इस पर समुचित चर्चा भी होगी और इसे अमल में लाने का पूरा प्रयास भी किया जाएगा। यह उन राज्य सरकारों के लिए भी एक सबक है जो मुफ्त बिजली की व्यवस्था के लिए अंधाधुंध खर्च कर रही हैं। अब रूफ टॉप सोलर की इस योजना से सरकारी खजाने पर लगातार बोझ डाले बिना टिकाऊ आधार पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी।

राजकोषीय विवेक और संयम : विपक्षी दल अक्सर यह कहते रहे हैं कि सरकार का कर्ज लगातार बढ़ रहा है। लेकिन समझना होगा कि कोविड-19 की मजबूरी के चलते केंद्र सरकार का कर्ज जीडीपी के 61 प्रतिशत पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद सरकार के राजकोषीय संयम के चलते, राजकोषीय घाटा घटते हुए अभी तक 56 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। इस वर्ष सरकार ने अपने कर्ज को पिछले साल से भी कम रखा है। इस बार केंद्र सरकार मात्र 14.13 लाख करोड़.रुपए का समग्र और मात्र 11.74 लाख करोड़ रुपए का निवल ऋण लेगी। समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार का कर्ज, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में और घटेगा और रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग को बढ़ा सकती हैं। इसका असर यह हो सकता है कि निवेशक भारत में और अधिक आकर्षित होंगे। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अंतरिम बजट की मर्यादा रखते हुए वित्त मंत्री ने राजकोषीय संयम को दर्शाते हुए सरकार की लोकलुभावन कल्याणकारी और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला दस्तावेज पेश किया है, लोक लुभावन योजनाएं नहीं, दीर्घकाल में देश के विकास और लोगों के कल्याण का ध्यान रखा गया है।

संपादक की कलम से

भारत-रत्न आडवाणी

पहले बिहार के 'जननायक' समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर और अब भाजपा के शिखर-पुरुष लालकृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत-रत्न' से नवाजने का निर्णय राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के दौर में लिया गया। यह सम्मान प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति देते हैं। आडवाणी को 'भारत-रत्न' देने पर राजनीति और धर्म के एक वर्ग को घोर आपत्ति है, क्योंकि वह उन्हें 'सांप्रदायिक नेता' मानता रहा है, लेकिन भाजपा की दृष्टि भिन्न है। भाजपा की स्थापना और बुलंदियों तक पहुंचाने में जिन दो राजनेताओं का प्रथम योगदान रहा है, उन्हें यह सम्मान देकर भाजपा सरकार ने अपना कत्त्तव्य निभाया है। आडवाणी न केवल भारत सरकार में 'लौह-पुरुष' की भूमिका में थे, बल्कि वह ही भाजपा के बुनियादी शिल्पकार और विस्तारक रहे। आज भाजपा देश की सबसे बड़ी, ताकतवर काडर वाली, सत्तारूढ़ पार्टी है, जिसने इन दो सम्मानों के जरिए 'मंडल बनाम कमंडल' वाली राजनीति को 'मंदिर और मंडल' की राजनीति में परिणत करने की कोशिश की है। यह भाजपा का नया राजनीतिक विस्तार साबित होगा। बहरहाल आडवाणी बहुआयामी, व्यापक-विविध प्रतिभाओं के राजनेता रहे हैं। वह छोटी-सी उम्र में आरएसएस के प्रचारक बने, पत्रकारिता भी की, सशक्त लेखक भी रहे, अध्ययनशील ताउम्र रहे और देश के उपप्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। गौरतलब यह है कि आडवाणी पर सक्रिय राजनीति के बावजूद एक दाग तक नहीं लगा। वह राजनीति में जिस शुचिता, ईमानदारी, मर्यादा और गरिमा के पक्षधर थे, उन्होंने उन मूल्यों को पूरी शिद्दत से निभाया। आज की राजनीति में ऐसे चमकदार, उजले चेहरे विलुप्त श्रेणी में हैं, लिहाजा आडवाणी को 'भारत-रत्न' देना सार्थक और सुखद लगता है।

वह कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। संसद के दोनों सदनों के सांसद रहे। लंबे समय तक उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभाई। अब 96 साल की उम्र में वह संन्यास की अवस्था में हैं, तो उनके परिवार का एक भी सदस्य राजनीति या सरकार में नहीं है। 'भारत-रत्न' देकर आडवाणी के बेदाग सार्वजनिक जीवन को अलंकृत किया गया है। दरअसल आडवाणी तब भारतीय राजनीति की धुरी बने, जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक की रथ-यात्रा निकाली थी। रथ-यात्रा पूरी नहीं हो सकी, लेकिन वह उस दौर की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक यात्रा साबित हुई। आडवाणी ने धर्म को राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, देशभक्ति से जोड़ा। सांप्रदायिक धुरवीकरण की चिंगारी भी यहीं से भडक़ी। हिंसा का दौर शुरू हुआ और सरकारों ने दमन-चक्र चलाया। नतीजतन राम मंदिर आंदोलन अधिक लामबंद, एकजुट और उग्र होने लगा। कथित बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया और भारतीय राजनीति का भविष्य भी तय कर दिया गया।

आडवाणी पर मस्जिद तोडने या भडक़ाने-उकसाने का आरोप पूर्वाग्रह हैं, क्योंकि तमाम रिकॉर्ड संरक्षित हैं कि उन्होंने और विहिप के अशोक सिंघल आदि ने कारसेवकों को मस्जिद पर चढने और उसे क्षति पहुंचाने को रोकने के आह्वान किए थे, लेकिन रामभक्तों के रोष, आक्रोश, आक्रामकता ने किसी की नहीं सुनी। शायद यही नियति थी! एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद यह विवादास्पद अध्याय ही बंद हो गया। अब तो राम मंदिर का एक हिस्सा बन चुका है और उसमें प्रभु श्रीराम की प्राण-प्रतिष्ठा भी की जा चुकी है। दरअसल यही वह दौर था, जब आडवाणी भाजपा के शिल्पकार साबित हुए और 1996 में पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। तब से आज तक भाजपा सर्वोच्च ही रही है। अब तो अकेले दम पर भी पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश हासिल है। आडवाणी भाजपा के संगठन-पुरुष थे। उन्होंने पार्टी में नेताओं की दूसरी पीढ़ी तैयार की। प्रधानमंत्री मोदी भी उसी पीढ़ी के सदस्य रहे हैं।

राय

नाव चली पानी की धार

भीगते मौसम के पहरे में राजनीति के हुंकारे जब धर्मशाला में इंद्रुनाग से प्रार्थना कर रहे थे, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत द्वार पर आगामी लोकसभा चुनाव के हरकारे तैनात रहे। निश्चित रूप से भाजपा ने धर्मशाला में अपना कद तौर-तरीके, संगठन शक्ति, जीत की लालसा और तैयारी का जज्बा दिखाया है। पिछले चुनावों में हिमाचल ने जो खोया, उसके सामने नए बीज बोती पार्टी ने कांग्रेस के सामने अपना राजनीतिक मानचित्र पेश कर दिया है। यहां दिल्ली के फैसलों की जमीन हिमाचल में टटोली जा रही है, जबकि इसके बरअक्स कांग्रेस को प्लान बनाने के लिए दरबार कहीं दिल्ली में सजाना पड़ा। राजनीतिक संभावना में कौशल, कत्त्तव्य, विमर्श और इच्छा शक्ति का प्रदर्शन भाजपा की तासीर है, तो कांग्रेस के अपने दंभ और संगठन से जूझता अपना ही सत्ता पक्ष और विरोध देखा जा रहा है। गिनती और गणित में फर्क भी यही है कि सियासत की छोटी सी सफलता गिनती है, लेकिन सफलता का गणित व्यापक है। इसलिए भाजपा ने सफलता का अपना व्याकरण तैयार कर लिया है और इसी के अध्याय धर्मशाला में पढ़े गए। पार्टी नीचे से ऊपर तक एक समान पाठ्यक्रम पढ़ रही है, जबकि कांग्रेस में कुछ आला लोगों के लिए अलग विषय और बाकियों के लिए इबारतें बदलती रहती हैं। लोकसभा की चार सीटों के चुनाव में भाजपा के इंतजाम, उसके संसाधन, लक्ष्यों की बुनियाद और सियासी वातावरण की पड़ताल में खुद से और मतदाताओं से संबोधित है। ऐसे में कांग्रेस के पास हिमाचल की सत्ता और सत्ता का प्रयोग मुखातिब है। यह एक साल की सरकार के व्यवहार, संकल्प, इरादे, दस्तूर और प्रशासनिक तौर-तरीकों का मुआयना है।

बेशक पिछले साल की चमक में प्राकृतिक आपदा का खलल रहा, लेकिन चांदनी तो पहाड़ की हर रात को दिशा देती रही। जाहिर तौर पर चुनाव में कांग्रेस की सत्ता रहेगी, तो संगठन का तालमेल भी देखा जाएगा। देखे जाएंगे सत्ता में लाभ के पद और पदों पर सुशोभित नेता। दूसरी ओर मंत्रियों और विधायकों के प्रदर्शन में बनते-बिगड़ते जनता के अनुभव। अफसरों के तहखानों में आंदोलनरत फाइलों के मुकदमे, व्यवस्था परिवर्तन के मुहाने और दफ्तरों में आते-जाते प्रश्नों के उत्तर भी तो चुनाव में ढूंढे जाएंगे। सरकार की कसौटियों और संतुलन मंत्रिमंडल के गठन, विस्तार और महकमों के आबंटन की खूबसूरती में रंगभर रही हैं, तो चिराग जलाने की कोशिश में हाथ न जलें यह चुनौती खड़ी है। मंत्रिमंडल की भीतरी तहें तो मुलायम हो गईं, मगर बाहर के खुरदरे प्रश्नों पर आबरू बचाने की मेहनत रहेगी। हैं रूठे दिल कहीं इस खेत में बिखरे, उगने से पहले बीज भी इश्क का मरीज है।

मंत्रिमंडल के भीतर सत्ता का साम्राज्य दुरुस्त हो रहा है, लेकिन इसके बाहर और तमाम विभागीय आबंटन के नीचे तड़प रहा है एक खाली पद। यह पद सताता है और इसके सामने कैबिनेट रैंक में घूम रहे राजनीतिक आशियाने पसर गए खाली जमीन पर। बहरहाल सरकार के आभामंडल में हर्षवर्धन, विक्रमादित्य सिंह, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, राजेश धर्माणी और यादविंद्र गोमा के नाम हुए नए विभाग सरकार की शक्ति का भी आबंटन है। यह शक्ति शिमला संसदीय सीट को सराबोर करती है, तो हमीरपुर के धुरव में स्वयं सिद्ध है। कांगड़ा संसदीय सीट की उलझनें अपने इतिहास में राजनीतिक कमी को सह रही हैं, तो मंडी के तिलक में कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह का गुलाल होली खेल सकता है। भाजपा और कांग्रेस के बीच उम्मीदवारों का चयन उन दीवारों का चयन भी है, जिनकी दूसरी तरफ विरोधियों के खेत में सूखा हो सकता है।

डिजिटल डिटॉक्स की सख्त जरूरत

अब समय आ गया है कि हम डिजिटल उपकरणों से विराम का बटन दबाएं और अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और शांति को फिर से खोजें और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाएं'

भागदौड़ वाली जिंदगी में डिजिटल उपकरण हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। हम स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और टीवी से हर समय घिरे हुए रहते हैं, जो हमें सूचना और मनोरंजन की एक अंतहीन धारा से जोड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि औसत व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे से अधिक समय स्क्रीन पर बिताता है। इस डिजिटल युग के बीच हम अक्सर उस पर्यावरण से जुडने के महत्व को भूल जाते हैं जो हमें स्वस्थ बनाए रखता है। यह अत्यधिक स्क्रीन समय न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बल्कि ऊर्जा की खपत और इलेक्ट्रॉनिक कचरे में भी योगदान देता है। आजकल एक नया शब्द सुर्खियों में है और वह है डिजिटल डिटॉक्स। आइए जान लेते हैं आखिर डिजिटल डिटॉक्स है क्या? डिजिटल डिटॉक्स का अर्थ है स्क्रीन-मुक्त समय के लिए डिजिटल उपकरणों को कुछ समय के लिए बंद करना। आजकल बहुत से लोग एक दिन या कुछ दिन या एक हफ्ते आदि के लिए डिजिटल डिटॉक्स का विकल्प चुन रहे हैं। इसके कई लाभ हैं। जैसे-जैसे अधिक से अधिक लोग स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल उपकरणों के आदी होते जा रहे हैं, डिजिटल डिटॉक्स इस भयानक लत के कुचक्र को तोड़ सकता है और इनसान ऑफलाइन समय के महत्व को समझ सकता है।

मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए डिजिटल डिटॉक्स बहुत मददगार है। आजकल डिजिटल उपकरणों के भारी उपयोग के कारण कई लोगों को तनाव यानी स्ट्रेस की समस्या हो रही है। इसी तनाव को कम करने का एक उपाय है डिजिटल डिटॉक्स। यह समय बचाता है, खासकर उन लोगों के लिए मददगार है जो डिजिटल उपकरणों पर बहुत समय बर्बाद करते हैं। यह उपकरण हमें सूचना संबंधी तनाव दे रहे हैं। हमें आदत हो गई है कि हम दो-दो मिनट बाद अपने फोन को अनलॉक करके सूचनाओं को खोजते रहते हैं। डिजिटल डिटॉक्स हमें सूचना खोज से मुक्ति दिलाता है। यह व्याकुलता-मुक्त समय देता है, जो दिमाग को रचनात्मक बनने में मदद करता है। फिर हम निरंतर सूचनाओं से विचलित हुए बिना वास्तव में अपने शौक और अन्य रुचियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे तनाव कम होता है क्योंकि मैसेज, ईमेल और कॉल का जवाब देने का दबाव नहीं होता। आजकल स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल के कारण लोगों के पास खाली समय कम हो गया है। डिजिटल डिटॉक्स हमें अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने में मदद करेगा। डिजिटल उपकरण नींद में खलल पैदा करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स हमें बेहतर नींद में मदद कर सकता है। अपने और अपने प्रियजनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स बहुत फायदेमंद है। यह हमें टेक्नोलॉजी की लत से छुटकारा पाने में मदद करता है। कुछ समय के लिए अपने डिजिटल उपकरणों को बंद करके, हम अपना कीमती समय रचनात्मक कार्य में लगा सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के साथ साझेदारी में डिजिटल डिटॉक्स अभियान शुरू किया है। इस पहल में गेमिंग और सोशल मीडिया पर विशेष जोर दिया गया है।

यह डिजिटल डिटॉक्स पहल लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य माइंड-फुलनेस को प्रोत्साहित करना, स्क्रीन समय कम करना, डिजिटल लत को कम करना और प्रौद्योगिकी के साथ स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना है। इस प्रक्रिया में कई गतिविधियां शामिल हैं, जैसे उपकरणों से अनप्लग करना, ऑफलाइन रहते हुए अपने शौक और गतिविधियों में शामिल होना, प्रकृति में समय बिताना और आमने-सामने सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना आदि। डिजिटल डिटॉक्स पहल को लेकर कर्नाटक सरकार की कई योजनाएं हैं। यह माइंडफुल टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के साथ सहयोग करेगा। कर्नाटक सरकार राज्य भर में डिजिटल डिटॉक्स केंद्र स्थापित करेगी। ये केंद्र प्रौद्योगिकी उपयोग के प्रबंधन में सहायता चाहने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित पेशेवरों से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आइए अब जान लेते हैं ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के बारे में, दरअसल यह फोरम ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के तहत भारतीय गेम डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गैर-लाभकारी समूह है।

हाल ही में किया गया एक शोध, प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग को खराब मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ता है, खासकर किशोरों के लिए। क्योंकि उनका मस्तिष्क अभी भी विकसित हो रहा है, वे शरीर और तंत्रिका तंत्र पर प्रौद्योगिकी के नकारात्मक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, अभिभावकों को अनप्लग करने के लाभों को समझना होगा, और किशोरों को अनप्लग करने में मदद करने के लिए रणनीतियों को सीखना होगा। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि मानसिक स्वास्थ्य पर प्रौद्योगिकी के कई नकारात्मक प्रभाव हैं, जैसे नींद की कमी और वास्तविक दुनिया से कम मेल-मिलाप। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अनप्लग करने के लाभों में बेहतर स्वास्थ्य, बाहरी गतिविधियों के लिए अधिक समय और वास्तविक जीवन के सामाजिक संबंधों में सुधार शामिल हैं। अभिभावक, किशोरों को स्क्रीन से छुटकारा पाने और स्क्रीन पर बिताए जाने वाले समय को कम करने में मदद करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। जब प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग चिंता या अवसाद का लक्षण बन रहा है या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा रहा है, तो उपचार आवश्यक है और यह उपचार डिजिटल डिटॉक्स से ही संभव है। अब समय आ गया है कि हम डिजिटल उपकरणों से विराम का बटन दबाएं और अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और शांति को फिर से खोजें और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाएं।

प्रत्यूष शर्मा

व्यंग्य पर भारत रत्न

सुबह की सैर के दौरान पीपल के पेड़ के पास से गुजऱते हुए अचानक झुन्नू लाल नीचे झुके और पीपल का एक पत्ता उठाने के बाद बड़े अदब के साथ मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, 'आप भारत रत्न के रूप में इसे तब तक स्वीकार करें, जब तक भारत सरकार की ओर से आपको व्यंग्य लेखन हेतु भारत रत्न सम्मान की घोषणा नहीं हो जाती।' उनके इस क़दम से अचकचा कर मैं कुछ बोलने वाला था कि वह दूसरी मिसाइल गिराते हुए कहने लगे, 'देश में लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। सम्मानों-पुरस्कारों का मौसम चल रहा है। कुछ को क़ब्रों से निकाल कर सम्मान चिपकाए जा रहे हैं और कुछ को,. क़ब्र में जाने से पहले। मैंने अपने सांसद और विधायक से निवेदन किया है कि वे भारत सरकार से भारत रत्न के लिए आपके नाम की संस्तुति करें ताकि हमारा गली-मोहल्ला भी गौरवान्वित महसूस कर सके।' उनकी हताशा को भाँपते हुए मैंने पूछा, 'लेकिन सरकार का ग़ुस्सा आप मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं?' वह बोले, 'अच्छा तो अब आप मुझसे यह हक़ भी छीन रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि अवाम के सामने ऐसे सवाल उठा कर मैं भी उमर ख़ालिद की तरह बिना ज़मानत के सालों तक जेल में पड़ा रहूँ और सुप्रीम कोर्ट के पास मेरी ज़मानत वाली याचिका पर सुनवाई का वक्त भी न हो।' उनके इज़हार में छिपी आम आदमी की पीड़ा को आत्मसात करते हुए मैंने कहा, 'चलें आप कम से कम मेरे सामने तो बोल रहे हैं। वर्ना आम आदमी विश्व गुरू होने के ग़ुरूर और अधूरे राम मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा की प्रसन्नता में भूखा और बेरोजग़ार होने के बावजूद गूँगा-बहरा हो गया है।' झुन्नू लाल बोले, 'कोई ज़माना था जब भारत रत्न से किसी बड़ी शख्सियत को विभूषित करने की घोषणा के बाद यह सम्मान ख़ुद को सम्मानित महसूस करता था। तब चुनावों के मौसम को देख कर नहीं, व्यक्ति के क़द को देख कर यह सम्मान दिया जाता था।

फिर सम्मानों पर चुनाव भारी पडऩे लगे। धीरे-धीरे एक समय ऐसा भी आया कि आज़ादी के चार-पाँच दशक गुजऱने के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन वीरों को क़ब्रों से उठाकर सम्मान दिया जाने लगा जिनकी ज़ात-बिरादरी या राज्य से वोट बटोरे जा सकते थे। इस दौर में एक ऐसे क्रिकेटर को भी भारत रत्न से नवाज़ा गया, सामाजिक मुद्दों पर जिसकी ज़बान अब स्वार्थ की यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड हो चुकी है। जब यह क्रिकेटर विज्ञापनों में सामान बेचता नजऱ आता है तो शर्म के मारे भारत रत्न अंतःपुर में जा छिपता है। अब मुझे डर है कि भारत सरकार सदी के उस कथित महानायक को किसी भी दिन भारत रत्न देने की घोषणा कर सकती है, जो सारी उम्र फिल्मों में नाचता-गाता रहा है।' उनकी परेशानी को भाँपते हुए मैं बोला, 'झुन्नू जी, आजकल तो व्यंग्य हमारे आसपास ही पसरा पड़ा है। लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप व्यंग्य का उपयोग मानव स्वभाव में मूर्खता और दुष्टता का मज़ाक उड़ाने के लिए करते हैं या सरकार और समाज की मूर्खता और दुष्टता में ख़ुद मज़ाक बन जाते हैं। परसाई जी कह गए हैं कि आत्मविश्वास धन का होता है, विद्या का भी और बल का भी, पर सबसे बड़ा आत्मविश्वास नासमझी का होता है। लोग अपनी मूर्खता, दुष्टता और स्वार्थ के कारण नासमझ हैं या नासमझी के कारण मूर्ख, दुष्ट और स्वार्थी। अगर इसी पर निरपेक्ष बात हो जाए तो व्यंग्य ख़ुद ब ख़ुद फूट पड़ता है।' मेरी बात सुनने के बाद वह मेरे हाथ में पीपल का एक और पत्ता थमाते हुए बोले, 'अब भारत सरकार की ओर से आप सचमुच यह भारत रत्न सम्मान सहर्ष स्वीकार करें।' उनके दिए गए पीपल के पत्ते को पकड़े मैं सोच रहा था कि यह वास्तव में मेरा सम्मान है या उस राजनीतिक गुरू का, जिसके चेले ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उसे मार्गदर्शक मंडल की खाई में धकेलने के बाद चुनावों से पूर्व उसे झाड़-पोंछ कर उसके हाथों में पीपल का पत्ता पकड़ा दिया है। यह मज़ाक है या व्यंग्य?

पेटीएम पर नहीं होगी कोई ईडी जांच, राजस्व सचिव ने की पुष्टि, यहां जानें डिटेल

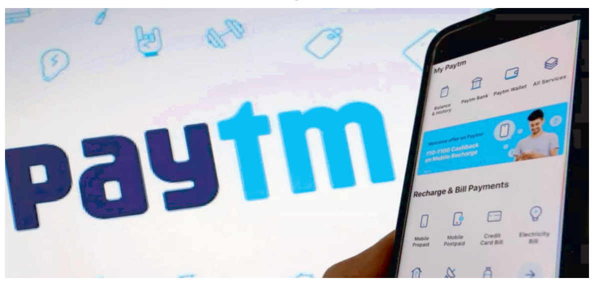

परिवहन विशेष न्यूज

पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने कंपनी और सीईओ पर ED के जांच की खबर को गलत बताते हुए अपना बयान दिया है। 4 फरवरी को कंपनी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से किसी भी जांच का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ये बात चर्चा में तब आई जब कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोप सामने आए है।

नई दिल्ली। पेटीएम बीते कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पता चला कि पेटीएम पर ED की कार्रवाई होने की आशंका है। मगर अब पेटीएम के राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने इस बात से इंकार कर दिया है।

मल्होत्रा ने बताया कि पेटीएम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच नहीं चल रही है न तो किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी ने फिनटेक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि ये बात तब सामने आई जब मीडिया रिपोर्टों में पेटीएम के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने की बात कही गई है।

मनी-लॉन्ड्रिंग में नहीं शामिल है कंपनी

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कोई कार्रवाई करनी होगी तो कानून प्रवर्तन एजेंसियां करेंगी। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है।

आपको बता दें कि पेटीएम ने खुद एक एक्सचेंज फाइलिंग में इस मामले को संबोधित किया और मनी-लॉन्ड्रिंग में भागीदारी से इनकार किया है।

इसके साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि हम भारतीय कानूनों का पालन करते हैं और नियामक आदेशों को गंभीरता से लेते हैं।

नहीं हो रही ED की जांच

कंपनी ने इस फाइलिंग में स्पष्ट किया गया कि न तो कंपनी और न ही इसके सीईओ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ED की जांच के दायरे में हैं। इसने अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ व्यापारियों/उपयोगकर्ताओं से पिछली पूछताछ को स्वीकार किया और ऐसी जांच के दौरान अधिकारियों के साथ सहयोग पर जोर दिया। आपको बता दें कि हाल ही में RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक के कुछ सर्विसेज के प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने ये बात भी कही कि 29 फरवरी के बाद भी पेटीएम ऐप लगातार काम किया है।

वॉलेट बिजनेस को नहीं खरीद रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, पेटीएम ने बातचीत से किया इनकार

हाल ही में एक नई जानकारी में पता चला है कि जियो शायद पेटीएम वॉलेट को खरीदने वाला है। मगर अब पेटीएम और जियो ने इसकी पुष्टि की है कि इन कंपनियों के बीच कोई ऐस बातचीत नहीं चल रही है। पेटीएम ने कहा कि हमें हमारी सहयोगी कंपनी पीपीबीएल ने सूचित किया है कि वे भी इस संबंध में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं।

नई दिल्ली। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्पष्ट किया है कि कंपनी पेटीएम वॉलेट के अधिग्रहण के लिए चर्चा में नहीं है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने उन रिपोर्टों के बाद स्पष्टीकरण दिया, जिन्हें कंपनी ने अटकलबाजी बताया था।

पेटीएम ने एक स्पष्टीकरण में यह भी कहा कि हम इस संबंध में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमें हमारी सहयोगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) ने सूचित किया है कि वे भी इस संबंध में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं।

RBI ने लगाई कुछ सेवाओं पर बैन

पहले के एक बयान में, वन 97 कम्युनिकेशंस (ओसीएल) ने कहा था कि उसे उसके सहयोगी पीपीबीएल द्वारा सूचित किया गया है कि आरबीआई ने 31 जनवरी, 2024 को अपने प्रेस वक्तव्य के जरिए यह जानकारी दी है। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत आगे निर्देश देता है।

पीपीबीएल आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठा रहा है, जिसमें उनकी चिंताओं को जल्द से जल्द दूर करने के लिए नियामक के साथ काम करना भी शामिल है।

कंपनी को सूचित किया गया है कि इससे उनके बचत खातों, वॉलेट, FASTags और NCMC खातों में यूजर्स की जमा राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जहां वे मौजूदा शेष राशि का उपयोग करना जारी रख सकते हैं।

अन्य बैंकों के साथ काम करेगी पेटीएम

OCL, एक भुगतान कंपनी के रूप में विभिन्न भुगतान प्रोडक्ट पर विभिन्न बैंकों (सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक नहीं) के साथ काम करती है। बयान में कहा गया है कि प्रतिबंध शुरू होने के बाद से ओसीएल ने अन्य बैंकों के साथ काम करना शुरू कर दिया है।

कंपनी ने कहा कि अब सेवा व्यवसाय, केवल अन्य बैंकों के साथ साझेदारी में आगे बढ़ते हुए योजनाओं में तेजी लाएंगे और पूरी तरह से अन्य बैंक भागीदारों के पास जाएंगा।

ओसीएल पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के अलावा अन्य बैंकों के साथ काम करेगा। ओसीएल की यात्रा का अगला चरण अपने भुगतान और वित्तीय विस्तार को जारी रखना है।

हम देश के कई अग्रणी बैंकों के साथ साझेदारी में व्यापारियों को अधिग्रहण सेवाएं प्रदान करते हैं और तीसरे पक्ष की बैंक साझेदारी का विस्तार करना जारी रखेंगे। पेटीएम पेमेंट गेटवे व्यवसाय (ऑनलाइन व्यापारी) अपने मौजूदा व्यापारियों को भुगतान समाधान प्रदान करना जारी रखेगा।

ओसीएल की ऑफलाइन मर्चेंट भुगतान नेटवर्क पेशकश जैसे पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंडबॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन, हमेशा की तरह जारी रहेगी, जहां यह नए ऑफलाइन व्यापारियों को भी शामिल कर सकती है।

पेटीएम के शेयर 5.5 फीसदी की बढ़त

सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर पेटीएम के शेयर 5.5 फीसदी की बढ़त के साथ 462.70 रुपये पर हैं। RBI के प्रतिबंधों के बाद पिछले कुछ सत्रों में पेटीएम के शेयरों में गिरावट आई थी।

कारोबार की कमजोर शुरुआत के बावजूद बीएसई पर स्टॉक 7.79 फीसदी उछलकर 472.50 रुपये पर पहुंच गया। वहीं एनएसई पर यह 7.99 प्रतिशत चढ़कर 473.55 रुपये पर पहुंच गया।

RBI की सख्ती के बाद पिछले तीन दिनों में स्टॉक में 42 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जिससे इसके बाजार मूल्यांकन से 20,471.25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

इनसाइड

बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार की राहत! आज से 29 रुपये प्रति किलो मिलेगा चावल, लॉन्च होगी ये योजना

पिछले साल अनाज की कीमतों में 15 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। ऐसे में अनाज की कीमतों को काबू करने के लिए आज सरकार Bharat Rice लॉन्च करेगी। इसमें 29 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर चावल दिया जाएगा। Bharat Rice में सब्सिडी वाला चावल 5 किलो और 10 किलो के पैक में उपलब्ध होगा।

नई दिल्ली। भारत में चावल की खुदरा कीमतों में पिछले एक साल में तेजी देखने को मिली है। ऐसे में भारत सरकार उपभोक्ता को राहत देने के लिए रियायती दर पर चावल की बिक्री करना शुरू कर रही है। आज सरकार द्वारा Bharat Rice लॉन्च किया जाएगा। इसमें उपभोक्ता को 29 रुपये प्रति किलोग्राम पर चावल दिया जाएगा। सब्सिडी वाला चावल 5 किलो और 10 किलो के पैक में उपलब्ध होगा। बता दें कि पिछले 1 साल में चावल की खुदरा कीमतों में 15 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है।

इन कैटेगरी में हेल्थकेयर हीरो को किया जाएगा सम्मानित

परिवहन विशेष न्यूज

Healthcare Heroes Awards and Conclave का चौथा संस्करण 22 फरवरी 2024 को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा जहां स्वास्थ्य की दुनिया से संबंधित लोग मौजूद रहेंगे। यह समारोह उन हेल्थकेयर हीरो के लिए है जिन्होंने अपने इनोवेशन से स्वास्थ्य के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। यह समारोह उनके लिए भी है जो अपने तरीके से लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार ला रहे हैं।

नई दिल्ली। हेल्थकेयर इनोवेशन कई वजहों से महत्वपूर्ण है। इसका महत्व न केवल हेल्थकेयर डिलिवरी से है बल्कि मरीजों को मिलने वाली बेहतर सुविधा, रोगों का पता लगाने और उसके निवारण से जुड़ा हुआ है। जैसे-जैसे विज्ञान और तकनीक का विकास हो रहा है, उसका लाभ चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है।

इस क्षेत्र में कई ऐसे हेल्थकेयर हीरो हैं, जो मानव जाति की सेहत को बेहतर बनाने के लिए लगातार इनोवेशन कर रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जागरण न्यू मीडिया का हेल्थ विंग onlymyhealth ऐसे ही हेल्थकेयर हीरो को सलाम करता है और 22 फरवरी 2024 को इनके इनोवेशन व काम को सम्मानित करने जा रहा है।

दरअसल, Healthcare Heroes Awards and Conclave का चौथा संस्करण 22 फरवरी 2024 को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य की दुनिया से संबंधित लोग मौजूद रहेंगे। यह समारोह उन हेल्थकेयर हीरो के लिए है, जिन्होंने अपने इनोवेशन से स्वास्थ्य के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए काम किया है।

इसके अलावा, यह समारोह उनके लिए भी है जो अपने तरीके से लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार ला रहे हैं। समारोह में सेलिब्रिटी स्पीकर के रूप में अभीनेत्री व वेलनेस एंटरप्रेन्योर पूजा बेदी को आमंत्रित किया गया है।

Healthcare Heroes Awards and Conclave 2024 में हेल्थकेयर हीरो को सम्मानित करने के लिए कई कैटेगरी बनाई गई है, आइए उसके बारे में जानते हैं।

मेंटल हेल्थ वॉरियर, कम्युनिटी हीरो, हेल्थ टेक स्टार्ट-अप, इनोवेशन इन डिजीज डायग्नोसिस, हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन ऑफ दी ईयर, आउट-ऑफ-द-बॉक्स फिटनेस, पोषण वॉरियर, सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस वॉरियर, वुमेन हेल्थ अवेयरनेस वॉरियर, मेन हेल्थ अवेयरनेस वॉरियर, जेंडर डायवर्सिटी वॉरियर, स्पेशल अवॉर्डः हेल्थ इन्फ्लुएंसर ऑफ दी ईयर, फिटनेस ऐप, हेल्थ-टेक वियरेबल्स और इनोवेटिव होम हेल्थकेयर प्रोडक्ट।

Healthcare Heroes Awards and Conclave 2024 में नॉलेज शेयरिंग सेशन और वन ऑन वन सेशन जैसे कार्यक्रम भी हैं, जहां स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें शामिल है - भारत के स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करना, डिजिटल शक्ति का लाभ उठाना, सोशल मीडिया के युग में मानसिक स्वास्थ्य, भारत में विकसित हो रहे हेल्थ केयर सिस्टम, आधुनिक तकनीक स्वास्थ्य सेवाओं को कर रही है पुनर्परिभाषित, पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन - आगे का रास्ता क्या है? आदि।

अगर आप हेल्थ इनोवेशन से जुड़े हुए हैं और देश की स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए काम कर रहे हैं या फिर आप लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं, तो यह समारोह आपके लिए है। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें- https://www.onlymyhealth.com/events/healthcare-heroes-awards

बदल गए सोने-चांदी के दाम, चेक करें आज आपके शहर में क्या है गोल्ड की कीमत

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में गोल्ड खरीदना काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा यह निवेश के लिए भी काफी पसंद किया जाता है। अगर आप भी सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको अपने शहर के लेटेस्ट रेट जरूर चेक करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोने-चांदी के क्या भाव है?

नई दिल्ली। Gold-Silver Price Today: भारत में गोल्ड खरीदना काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा यह निवेश के लिए भी काफी पसंद किया जाता है।

कारोबारी दिनों में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है। यह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर हो रहे ट्रेडिंग के हिसाब से तय किया जाता है। आज भी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के नई कीमत जारी हो गए हैं।

सस्ता हुआ सोना

विदेशी बाजारों से मंदी के संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोने की कीमतें 150 रुपये गिरकर 63,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं। पिछले बंद में सोना 63,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

वैश्विक बाजारों में सोना गिरावट के साथ 2,022 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटी के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा

विदेशी बाजारों से मंदी के संकेत लेते हुए, दिल्ली के बाजारों में सोने की हाजिर कीमतें (24 कैरेट) 150 रुपये की गिरावट के साथ 63,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही हैं।

कम हुई चांदी के दाम

आज चांदी भी 600 रुपये गिरकर 74,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई, जबकि पिछले कारोबार में यह 75,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वैश्विक बाजारों में चांदी गिरावट के साथ 22.32 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

क्या है आपके शहर में सोने की कीमत

दिल्ली में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,150 रुपये है।

मुंबई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,000 रुपये है।

आरबीआई के रेट सेटिंग पैनल ने शुरू किया विचार-विमर्श; 8 फरवरी को आएगा फैसला

परिवहन विशेष न्यूज

रिजर्व बैंक ने करीब एक साल से अल्पकालिक ऋण दर या रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर स्थिर रखा है। मुख्य रूप से वैश्विक विकास से प्रेरित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर आखिरी बार फरवरी 2023 में 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दी गई थी। RBI के रेट सेटिंग पैनल ने विचार-विमर्श शुरू किया। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाले दर-निर्धारण पैनल ने मंगलवार को अल्पकालिक ऋण दरों पर यथास्थिति जारी रहने की उम्मीद के बीच अपना तीन दिवसीय विचार-विमर्श शुरू किया। इसका कारण यह है कि खुदरा मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के सुविधा क्षेत्र के उच्चतम स्तर के करीब बनी हुई है।

रिजर्व बैंक ने करीब एक साल से अल्पकालिक ऋण दर या रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर स्थिर रखा है। मुख्य रूप से वैश्विक विकास से प्रेरित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर आखिरी बार फरवरी 2023 में 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दी गई थी।

खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट

जुलाई 2023 में 7.44 प्रतिशत के शिखर को छूने के बाद चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट आई है, यह अभी भी उच्च है और दिसंबर 2023 में 5.69 प्रतिशत थी, हालांकि रिजर्व बैंक के 4-6 प्रतिशत के आरामदायक क्षेत्र के भीतर है।

आपको बता दें कि गवर्नर दास गुरुवार (8 फरवरी) सुबह मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के फैसले की घोषणा करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एक रिपोर्ट में कहा कि आरबीआई को आगामी नीति में अपना ठहराव रुख जारी रखने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि मजबूत अमेरिकी गैर-कृषि पेरोल डेटा और वेतन ने दरों में त्वरित कटौती के लिए बाजार की उम्मीदों को पीछे धकेल दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि मेज पर पहली दर में कटौती जून से अगस्त की अवधि में हो सकती है। राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता को यह भी उम्मीद है कि आरबीआई आवास रुख को वापस लेना जारी रखेगा। एसबीआई ने आगे कहा कि सीपीआई 2023-24 में 5.4 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष (2024-25) में 4.6 प्रतिशत से 4.8 प्रतिशत के आसपास आने की उम्मीद है।

सरकार ने केंद्रीय बैंक को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दोनों तरफ 2 प्रतिशत के मार्जिन के साथ 4 प्रतिशत पर बनी रहे।

बनी रहेगी मौजूदा ब्याज दरें

नीति से उम्मीदों पर एंड्रोमेडा लोन के सह-सीईओ राउल कपूर ने कहा कि आरबीआई को मौजूदा ब्याज दरों को बनाए रखने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय मुख्य रूप से उच्च खुदरा मुद्रास्फीति की लगातार चुनौती से प्रभावित है, जो आरबीआई के मुद्रास्फीति लक्ष्य 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के असुविधाजनक रूप से करीब बनी हुई है। मौजूदा मुद्रास्फीति के दबाव के कारण सतर्क दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

एमपीसी को विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत रेपो दर तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मई 2022 में एक ऑफ-साइकिल बैठक में, एमपीसी ने नीति दर में 40 आधार अंकों की बढ़ोतरी की और इसके बाद फरवरी 2023 तक हर पांच बाद की बैठकों में अलग-अलग आकार की दरों में बढ़ोतरी की गई। रेपो दर में 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई मई 2022 और फरवरी 2023 के बीच संचयी रूप से अंक।

एमपीसी में तीन बाहरी सदस्य और आरबीआई के तीन अधिकारी शामिल हैं। पैनल में बाहरी सदस्य शशांक भिडे, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा हैं। गवर्नर दास के अलावा, एमपीसी में अन्य आरबीआई अधिकारी राजीव रंजन (कार्यकारी निदेशक) और माइकल देबब्रत पात्रा (डिप्टी गवर्नर) हैं।

मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कदम उठा रही है सरकार: सीतारमण

राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए गामा किरणों के माध्यम से प्याज को नमीमुक्त करने पर सरकार के साथ काम कर रहा है। मंत्री ने कहा कि प्याज की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के लिए सरकार ने इसके बफर आकार को 2020-21 में बढ़ाया था।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति सहनशीलता सीमा के भीतर आ गई है।

सरकार ने किया बीएआरसी से करार

राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए, सीतारमण ने कहा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए गामा किरणों के माध्यम से प्याज को नमीमुक्त करने पर सरकार के साथ काम कर रहा है।

उन्होने कहा कि सरकार उन कठिनाइयों से अवगत है, जो खराब होने वाली वस्तुओं की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं, जो भारत में नहीं उगाई जाती हैं। समिति समय-समय पर बैठती है और समीक्षा करती है, और प्रयासों से जमीन पर पता चला है कि मुद्रास्फीति अब सहनीय सीमा के भीतर है।

खुदरा मुद्रास्फीति में आई गिरावट

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल-दिसंबर 2022 में औसतन 6.8 प्रतिशत से घटकर 2023 की इसी अवधि में 5.5 प्रतिशत हो गई है। खुदरा मुद्रास्फीति अब स्थिर है और 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के अधिसूचित सहनशीलता बैंड के भीतर है।

मंत्री ने कहा कि प्याज की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के लिए, सरकार ने इसके बफर आकार को 2020-21 में 1 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से बढ़ाकर 2023-24 में 7 एलएमटी कर दिया है। 3 फरवरी, 2024 तक कुल 6.32 एलएमटी प्याज की खरीद की गई और 3.96 एलएमटी ग्रेड-ए प्याज खुदरा बिक्री, ई-नाम नीलामी और थोक बिक्री के माध्यम से जारी किया गया।

भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशियों का पैनल तैयार...

भाजपा ने राज्यसभा प्रत्याशियों के लिए 35 नामों की एक सूची तैयार कर ली है। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री के साथ अन्य नेताओं के नाम भी शामिल हैं।

लखनऊ। भाजपा राज्यसभा की सात सीटों के लिए पैनल में शामिल 35 दावेदारों के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी। यह पैनल मुख्यमंत्री आवास पर सोमवार रात आयोजित पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में चर्चा के बाद तैयार किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक विधानसभा, विधान परिषद सदस्य बनने से वंचित रहे प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ अन्य पदाधिकारियों के नाम पैनल में हैं। इसमें मौजूदा राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी, विजयपाल सिंह तोमर का नाम भी है। पैनल पर शीर्ष नेतृत्व अंतिम निर्णय लेकर 13 फरवरी तक सूची घोषित कर सकता है। राज्यसभा में दस सीटों पर होने वाले चुनाव में तीन पर सपा और सात पर भाजपा की जीत तय है। आठवीं सीट के लिए भी पार्टी नामांकन दाखिल कर सकती है।

बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 फरवरी को मुजफ्फरनगर के शुक्रताल से ग्राम परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। बैठक में गांव चलो अभियान, ग्राम परिक्रमा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिये महिला संपर्क और लाभार्थी संपर्क अभियान की प्रगति पर चर्चा की गई।

17-18 फरवरी को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारी पर भी बात हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी सहित अन्य नेताओं के दौरों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे।

बैजयंत पांडा का इंतजार

लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त प्रभारी एवं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा के यूपी में पहले दौरे का इंतजार है। पांडा को 27 जनवरी को प्रभारी नियुक्त किया गया था। लोकसभा चुनाव की घोषणा में करीब 40 दिन का समय है।

अब महज 6.79 लाख रुपये में ही इलेक्ट्रिक कार

नई दिल्ली। एमजी मोटर इंडिया की कॉमेट ईवी अब तक 7.98 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस में बिक रही थी, वह अब महज 6.99 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर उपलब्ध है। भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार एमजी कॉमेट के बेस मॉडल के दाम में लगभग एक लाख रुपये तक की कटौती की गई है, जिसके बाद इसकी एक्स शोरूम कीमत महज अब 6.99 लाख से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट की कीमत महज 8.58 लाख है। इस कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक हैचबैक की सिंगल चार्ज बैटरी रेंज 230 किलोमीटर तक की है।

अगले तीन दिन तक शीतलहर से फिर कांपेगा उत्तर भारत, न्यूनतम पारे में आएगी गिरावट

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टरबेंस की हलचल शुरू हुई है। हालांकि इस बार इसका असर उत्तर भारत की बजाय उत्तर-पूर्व के हिस्से वाले राज्यों में दिखाई देने का अनुमान लगाया जा रहा है...

नई दिल्ली। कुछ दिनों से लगातार हुई बारिश के बाद रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। दो दिन से दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में लगातार धूप निकल रही है। लेकिन मौसम विभाग के अनुमान मुताबिक मंगलवार रात से तापमान में तीन से चार डिग्री की कमी दर्ज होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मंगलवार देर शाम से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने का अनुमान है, जो कि अगले तीन दिन तक बनी रहेंगी। मौसम का यह बदलाव अगले तीन दिन तक बना रहेगा। विभाग के अनुमान के मुताबिक मुताबिक शुक्रवार सुबह तक उत्तर भारत के मैदानी इलाके शीतलहर की चपेट में रह सकते हैं।

भाजपा ने जिले में किया लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद

भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा को देश में सर्वाधिक मतों से जीत दिलानी है - पंचारिया

परिहवन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद भाजपा जिला संगठन ने कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आयोजित बैठक में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश चुनाव संचालन समिति संयोजक व क्लस्टर प्रभारी नारायण पंचारिया के मुख्य आतिथ्य, जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता, जिला प्रभारी रतनलाल गाडरी, विधायक लादूलाल पीतलिया, लालाराम बैरवा, गोपाल खंडेलवाल, गोपीचंद मीणा, पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर मंचासीन रहे।

जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्वगुरु बनाने की कल्पना के साथ कहा है कि 2024 का चुनाव आने वाले एक हजार वर्षों के लिए मजबूत नीव रखने वाला साबित होगा। अपने जिले में भी लोकसभा चुनाव की इस प्रकार तैयारी करनी है कि भीलवाड़ा देश में सर्वाधिक मतों से जीत वाली लोकसभा सीट बन जाए। प्रदेश में लोकसभा कार्यालय खोलने में भी भीलवाड़ा प्रथम जिला रहा है, इसी प्रकार प्रदेश द्वारा निर्देशित श्री राम मंदिर दर्शनाथ कार्यक्रम अभियान, नव मतदाता अभियान, शक्ति वंदन अभियान, दीवार लेखन अभियान, लाभार्थी संपर्क अभियान, पार्टी ज्वाइनिंग अभियान में भी जिले को प्रथम स्थान पर लाना है। हम सभी को सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ राष्ट्र निर्माण के इस अभियान में सहभागी बनना है।

बैठक के प्रारंभ में जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भीलवाड़ा को कांग्रेस मुक्त जिला बनाया है उसी प्रकार लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को भीलवाड़ा में ऐतिहासिक जीत दिलानी है। जिला प्रभारी रतनलाल गाडरी ने कहा कि जिले के कमजोर बूथों पर विशेष ध्यान देते हुए जिला स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख, पेज समिति प्रमुखों तक सभी को मजबूत करना है। बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद त्रिपाठी ने किया। अंत में आभार जिला महामंत्री भगवतीप्रसाद जोशी ने व्यक्त किया।

बैठक में जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल आचार्य, शंकरलाल जाट, सुखलाल गुर्जर, मुकेश धाकड़, लक्ष्मण सिंह राठौड़, अविनाश जीनगर, मंजू चेचाणी, छैलबिहारी जोशी, जिला मंत्री सुरेंद्र सिंह मोटरास, गोपाल तेली, अमरसिंह चौहान, राधेश्याम कुमावत, जिला कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल, जिला मीडिया संयोजक महावीर समदानी, अध्यक्षीय विभाग संयोजक मनोज बुलानी, विधानसभा संयोजक अनिल पारीक, मणिराज सिंह, शिवराज कुमावत, अनिल जैन, गोविंद सिंह, कन्हैयालाल जाट, मोर्चा अध्यक्ष मंजू पालीवाल, राजेश सेन, कुलदीप शर्मा, पूरण डीडवानिया, इमरान कायमखानी, महेंद्र मीणा, अभियान संयोजक रोशन मेघवंशी, भरतसिंह राठौड़, विजयपाल सिंह, सहसंयोजक मुकेश चेचाणी, आरती कोगटा, उदयलाल गाडरी, रमेश नवहाल, ज्योति आशीर्वाद सहित जिले के विस्तारक, मंडल अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

{माणिक्य-मोती-मूंगा-पन्ना रत्न}

रत्न धारण करने से आते हैं बदलाव

किसी भी व्यक्ति के जीवन में रंग और तरंग का सर्वाधिक महत्व होता है। रत्न भी इन्ही रंगों और तरंगों के माध्यम से प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति के शरीर के सात चक्र इन्ही रंगों और तरंगों को ग्रहण करते हैं। रत्नों के प्रयोग से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में बदलाव हो जाता है। रत्नों का असर शरीर के साथ ही मन और कार्यों पर भी पड़ता है। शुद्ध व उचित मुहूर्त पर पहने हुए रत्न ही काम करते हैं।

आइए जानते हैं कि कौन सा रत्न किस ग्रह का होता है-:

माणिक्य- सूर्य का रत्न-:

सूर्य से सम्बंधित समस्याओं के निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धुन, मीन लग्न के जातक के लिए माणिक रत्न शुभ होता है। लेकिन कुंडली में सूर्य की स्थिति का अवलोकन करने के उपरांत ही रत्न धारण करना चाहिए। कन्या, तुला, मकर, और कुम्भ लग्न वालों को कभी माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। अगर माणिक्य नुकसान करे तो सिरदर्द और हड्डियों में दर्द होने लगता है।

माणिक रत्न के साथ नीलम, गोमेद, लहसुनिया इत्यादि रत्न धारण नहीं करना चाहिए।

मोती- चन्द्रमा का रत्न-:

मन और शीतजन्य समस्याओं के निवारण में यह अदभुत काम करता है, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धुन, मीन लग्न के जातक के लिए मोती रत्न शुभ होता है। लेकिन कुंडली में चंद्रमा की स्थिति का अवलोकन करने के उपरांत ही रत्न धारण करना चाहिए।

वृष, मिथुन, कन्या और मकर लग्न में यह विपरीत परिणाम दे सकता है। मोती अगर नुकसान करे तो मानसिक स्थितियां बिगड़ने लगती हैं।

मोती रत्न के साथ पन्ना- नीलम- गोमेद- लहसुनिया इत्यादि रत्न धारण नहीं करना चाहिए।

मूंगा- मंगल का रत्न-:

ज्योतिष में लाल और नारंगी रंग के मूंगे का ज्यादा प्रयोग होता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धुन, मीन लग्न के जातक के लिए मूंगा रत्न शुभ होता है। लेकिन कुंडली में मंगल की स्थिति का अवलोकन करने के उपरांत ही रत्न धारण करना चाहिए।

मिथुन और कन्या लग्न वालों को मूंगा भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। मकर व कुंभ लग्न वालों के लिए भी मूंगा धारण करने से पहले गहन कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। जो लोग स्वभावतः क्रोधी हों, उन्हें लाल मूंगा नहीं पहनना चाहिए। मूंगा रत्न धारण करने से पहले विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

मूंगा रत्न के साथ पन्ना- गोमेद- लहसुनिया- नीलम इत्यादि भूलकर भी धारण नहीं करना चाहिए।

पन्ना- बुध का रत्न-:

यह बुध ग्रह को मजबूत करता है, पन्ना रत्न वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ लग्न के जातकों के लिए शुभ होता है कुंडली में बुध की स्थिति देखने के उपरांत इस रत्न को पहना जा सकता है।

परन्तु मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक, धनु, मीन लग्न में इसके परिणाम अशुभ हो सकते हैं। पन्ना धारण करने से अगर त्वचा में समस्या दिखे, तो इसे उतार दें।

पन्ना रत्न के साथ मोती- मूंगा- पुखराज रत्न धारण नहीं करने चाहिए।

नोट-:

रत्न का गलत संयोग बड़ा नुकसान दे सकता है जैसे-: मूंगे के साथ नीलम खतरनाक होता है। ध्यान रहे जब दो रत्न पहने तो उसका संयोग उचित होना चाहिए।

कोई भी रत्न उचित मुहूर्त पर पहनने पर ही शुभ फल प्रदान करते हैं। रत्न पहनने से पहले मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें।।

अब किसानों के मन की बात सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संकल्प पत्र में अन्नदाताओं की होगी बड़ी भूमिका

भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने बताया कि ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत 12 फरवरी को मां शाकंभरी देवी मंदिर मुजफ्फरनगर से होगी। यात्रा का शुभारंभ गाय, ट्रैक्टर, हल के पूजन के साथ प्रारंभ होगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे...

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसानों के मन की बात सुनेंगे। भाजपा 12 फरवरी से ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इस यात्रा के अंतर्गत देश के लगभग दो लाख गांवों में सभाएं कर किसानों की बात सुनी जाएगी। उनसे उनकी परेशानियों और आकांक्षाओं के विषय में पूछा जाएगा। किसानों से प्राप्त यह जानकारी भाजपा के संकल्प पत्र में सम्मिलित किया जाएगा। भाजपा का दावा है कि इससे किसानों की बातों को संकल्प पत्र का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक क्षमता बढ़ाना और क्षेत्रवार किसानों के लिए नीतियां बनाना है।

इस यात्रा के दौरान किसानों से प्राप्त सभी सुझावों को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को सौंपा जाएगा। यात्रा के दौरान डोर टू डोर कैंपेन चला कर मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रहीं कल्याणकारी योजनाओं के पत्रक भी लोगों को बांटे जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में एक बड़ी जनसभा का आयोजन भी कराए जाने की योजना है।

भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने बताया कि ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत 12 फरवरी को मां शाकंभरी देवी मंदिर मुजफ्फरनगर से होगी। यात्रा का शुभारंभ गाय, ट्रैक्टर, हल के पूजन के साथ प्रारंभ होगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस अवसर पर वे मजदूरों और किसानों की महासभा को भी संबोधित करेंगे।

किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मनोज यादव ने अमर उजाला को बताया कि यह यात्रा एक माह तक चलेगी। यात्रा में पीएम मोदी के द्वारा किसानों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में दो लाख से अधिक गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका डिजिटल प्रसारण भी किया जाएगा।

मनोज यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी दस साल की सरकार में किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। मिलेट फूड, प्रसंस्कृत खाद्य और नैनो खादों के प्रयोग को बढ़ावा देकर किसानों की कृषि लागत कम करने और आय बढ़ाने का प्रयास किया है। अब अगले कदम के रूप में किसानों को आर्थिक तौर पर ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाने हैं। इसके लिए सबसे पहले किसानों की बात सुनी जाएगी। यह यात्रा इसी क्रम में आयोजित की जा रही है।

अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर ने किया विद्युत विभाग के कार्यालयों का औचक निरीक्षण

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा। कार्यालय में निर्धारित समय से अधिकारियो तथा कार्मिको के पहुँचने के अनुशासन को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर श्री मुकेश कुमार मीणा ने मंगलवार को प्रातः 9.30 से 10.00 बजे के बीच ज़िले के विद्युत विभाग के कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता कार्यालय में अधीक्षण अभियंता श्री बाबूलाल स्वयं सहित 3 कार्मिक भी अनुपस्थित पाए गए। इसी प्रकार अधिशाषी अभियंता कार्यालय के 2 कार्मिक तथा सहायक अभियंता कार्यालय से भी 1 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। उक्त अधिकारी तथा कार्मिको को कार्यालय समय के दौरान कार्यालय में अनुपस्थित पाए जाने पर अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

अमृतसर फोकल पॉइंट वेलफेयर एसोशिएशन और पिंजरापोल गौशाला के शिष्टमंडल ने नगरनिगम कमीश्नर से की मीटिंग

अमृतसर (साहिल बेरी) हरप्रीत सिंह को फोकल पॉइंट में आ रही मुश्किलों के बारे में और अमृतसर में सड़कों पर घूम रहीं गायों के लिए गौशाला में शेड बनाने को लेकर ज्ञापन दिया इस अवसर पर प्रधान संदीप खोसला, और नवल गुप्ता ने कहा कि फोकल पॉइट में सफाई को लेकर बहुत मुश्किल ही और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां भी नहीं आ रही इस के साथ उन्होंने कमिश्नर को सड़को पर घूम रही गायों के लिए गोशाला में शेड बनाने को फंड देने के लिए सरकार से मांग रखी है इस अवसर पर चरणजीत शर्मा, राजेश कुमार लाडी, अशोक कपूर, भूपिंदर खोसला, आदि मोजूद थे।

ओडिशा मे भारत जोड़ न्याय यात्रा प्रवेश करेगा

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: कांग्रेस अपनी भारत जोड़ न्यययात्रा पर ओडिशा में प्रवेश करेगी। झारखंड के बसजोल के बाद यह अभियान सुंदरगढ़ के बीरमित्रपुर पहुंचेगा। बीरमित्रपुर के बीजाबहाल में रात्रि विश्राम। कल सुबह राउरकेला उदित शहर से मार्च शुरू होगा। सुबह 10 बजे पानपोसा में आमसभा होगी। दोपहर 2 बजे राजगांगपुर रानीबांध में आमसभा के बाद कुतरा और बरगा जायेंगे। शाम साढ़े चार बजे जुलूस बस स्टेशन वाली गली से शुरू होकर स्टेट बैंक गली तक जाएगा। आमसभा का कार्यक्रम है। 8 तारीख को झारसुगुड़ा में आमसभा का कार्यक्रम है। 14 जनवरी को मणिपुर के थौबुल जिले के खोंगजोम से शुरू हुई यात्रा 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। यात्रा 66 दिनों तक चलेगी. यह 15 राज्यों के 110 जिलों, 100 लोकसभा और 337 विधान सभा क्षेत्रों से होकर करीब 6 हजार 700 किलोमीटर गुजरेगी।

'राज्य सरकार गैर-उड़िया शासन का मुकाबला करने के लिए भाषा प्रेम दिखा रही है

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वर् : विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन भुबनेश्वर में। प्रचार-प्रसार सशक्त है। 100 करोड़ का खर्च। विद्यालय में उड़िया पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है। कॉलेज में भी शिक्षकों की कमी है।

आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के करीब 8 हजार 89 हाई स्कूलों में 10 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं. यह भी आश्चर्य की बात है कि दोनों राज्यों के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्कूलों में भी ओडिया विभाग नहीं है। कालाहांडी यूनिवर्सिटी में 7 प्रोफेसर और असिस्टेंट के पद थे लेकिन कोई नहीं बचा. विश्व के प्रमुख बिस्वाबिद्यालय रिवेंसा में एक प्रोफेसर और 2 एसोसिएट प्रोफेसर के पद रिक्त हैं।

इस बीच सरकार परिक्रमा परियोजना की तरह भाषा सम्मेलन को भी बढ़ावा दे रही है। गांव-गांव कार्यक्रम, स्कूल कॉलेज प्रतियोगिता। इसके लिए प्रति पंचायत 20,000 रुपये और प्रखंड स्तर पर 50,000 रुपये खर्च के लिए आवंटित किये गये हैं. वहीं, एसजीएच ब्लॉक फेडरेशन ने इसके लिए 20 हजार रुपये दिये हैं. विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में भाषा साहित्य के मुद्दे का मुकाबला करने के लिए भाषा सम्मेलन का आयोजन किया है, क्योंकि यह ओडिशा में गैर-उड़िया शासन के विरोध का मुख्य मुद्दा है।

आई माता मन्दिर, कोरेमुला बडेर में मुरलीधर राव जी का का स्वागत समारोह

ब्यूरो चीफ जगदीश सीरवी

तेलंगाना। हैदराबाद श्री आईमाता जी मन्दिर (बडेर) कोरेमुला में सीरवी समाज द्वारा लोकसभा मल्काजगीरी के प्रत्याशी मुरलीधर राव का सीरवी समाज द्वारा स्वागत सम्मान किया। ओर लोकसभा चुनाव में सहयोग का समाज ने वादा किया।, समाज के लोगों ने मुरलीधर राव से समाज बन्धुओं के लिए ट्रेन को प्रतिदिन करने का माँग किया हैं। सीरवी समाज को ओबीसी में लाने के लिए भी माँग किया हैं। आखिल भारतीय सीरवी समाज के प्रांतीय अध्यक्ष श्री हजारीराम काग एवं कोरेमुला बडेर के अध्यक्ष कालुराम काग सचिव डायाराम लचेटा एवं कार्यकारणी सदस्य, हैदराबाद सभी बडेर अध्यक्ष, सचिव एवं कार्यकारणी सदस्य आखिल भारतीय युवा मंच एवं सीरवी समाज संस्था के भी सदस्य कार्यक्रम का हिस्सा बने। गायत्री परिवार के उत्तम गायकवाड़ जी ने गायत्री मंत्र के द्वारा सब को भारतीय संस्कृति से जोड़ा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023